दिसंबर 2017 मासिक करेंट अफेयर्स संग्रह

प्रीलिम्स फैक्ट्स

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation - NSDC) और पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र कौशल परिषद (Tourism and Hospitality Sector Skill Council - THSC) ने दुनिया की अग्रणी समुदाय-संचालित आतिथ्य कंपनी एयरबन्ब के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के बीच हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता ज्ञापन भारत में आतिथ्य माइक्रो उद्यमियों के लिये आतिथ्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

- इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, इससे रोज़गार के अवसरों का सृजन होगा।

एन.एस.डी.सी. के बारे में

- एन.एस.डी.सी., कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का प्रमुख कार्यान्वयन निकाय है।
- एन.एस.डी.सी., कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत, भारत में अपनी तरह का एक सार्वजनिक, निजी भागीदारी (पीपीपी) वाला मॉडल है।
- इसका उद्देश्य बड़े, गुणवत्तापूर्ण और लाभप्रद व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

भारत उच्च रक्तचाप प्रबंधन पहल (India Hypertension Management Initiative – IHMI)

हाल ही में भारत उच्च रक्तचाप प्रबंधन पहल (India Hypertension Management Initiative - IHMI) का शुभारंभ किया गया।

- आई.एच.एम.आई. का लक्ष्य हृदय रोग संबंधी बीमारी (**cardiovascular disease - CVD**) से होने वाली मौत और विकलांगता को कम करने के लिये उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में सुधार करना, नमक की खपत को कम करना और कृत्रिम ट्रांस-वसा को नष्ट करना है।
- यह उच्च रक्तचाप के मापनीय उपचार के पाँच आवश्यक घटकों पर केंद्रित एक पहल है।
- यह उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिये मानकीकृत एवं सरलीकृत उपचार योजनाओं को अपनाने का समर्थन करती है।।

भारतीय वायुसेना की असाधारण उपलब्धि

भारतीय वायुसेना की त्वरित चेतावनी और नियंत्रण (Airborne Early Warning and Control- AEW&C) का कार्य करने वाले एमब्रियर परिवहन विमान में एमब्रियर प्लेटफार्म पर पहली बार हवा में ईंधन भरा गया है।

- हवा में ही ईंधन भरने की पद्धति यानी "प्रोब और ड्रोग" पद्धति (**"Probe and Drogue" air-to-air refuelling methodology)** में पायलटों के असाधारण उड़ान कौशल की आवश्यकता होती है।
- ऐसा इसलिये, क्योंकि ईंधन देने वाले विमान को ईंधन भरने वाले विमान के टैंकर के पीछे स्थित टोकरीनुमा संरचना को तलाश कर उसमें सटीक तरीके से ईंधन डालना होता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया के दौरान दोनों, ही विमानों में सटीक उड़ान मानदंड कायम रखे जाते हैं। ऐसी क्षमता दर्शाने वाली दुनिया की कुछ वायु सेनाओं में से एक भारतीय वायुसेना भी है।

कामोव-226टी' बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर

- भारत और रूस के बीच हुए 'कामोव-226टी' बहुउद्देशीय सैन्य हेलीकॉप्टर के सौदे में तकनीक हस्तांतरण और उत्पादन की प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी।
- 'कामोव-226टी' दो इंजन वाला एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है, जिसका प्रयोग सैन्य और नागरिक दोनों ही उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है।
- 'कामोव-226टी' भारत के चीता और चेतक के पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े की जगह लेगा।

सीआईटीईएस द्वारा सम्मानित हुआ भारत

- हाल ही में अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने के अपने क्षेत्रीय और वैश्विक प्रयासों के लिये भारत को सीआईटीईएस ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
- विदित हो कि यह सम्मान वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (**Wildlife Crime Control Bureau**) को दिया गया है।
- जिनेवा में सीआईटीईएस की **69**वीं स्थायी समिति की बैठक में भारत यह सम्मान पाने वाला एकमात्र देश है।
- सीआईटीईएस का उदेश्य लुप्त होने वाले वन्यजीवों एवं पादपों को सुरक्षित करना है।

अकालग्रस्त लेसोथो को भारत ने भेजी मदद

हाल ही में भारत ने 'किंगडम ऑफ लेसोथो' को 500 मीट्रिक टन चावल की एक खेप भेजी है, जो कि भीषण अकाल के कारण खाद्य संसाधनों की कमी से जूझ रहा है।

- लिसोथो जिसे लिसूतू और आधिकारिक तौर पर 'लिसूतू किंगडम' भी कहा जाता है, एक लैंडलॉक और 'दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र' से चारों तरफ से घिरा हुआ देश है।
- देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर मासेरु है। यह राष्ट्रमंडल का सदस्य है। लेसोथो का अर्थ मोटे तौर पर "सेसोथो बोलने वाले लोगों का देश" है।
- यहाँ बन्टू जाति के बासूतो लोग रहते हैं। इसकी पूर्वी सीमा पर **10** हज़ार फुट ऊँचा 'ड्राकेन्सबर्ग' नामक पठार है और ऑरेंज यहाँ की प्रमुख नदी है।
- यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, मक्का, जौ, बीन और मटर आदि हैं। हाइलैंड पठार के कारण कठिन मौसमी परिस्थितियों तथा लोलैंड में कृषि हेतु सीमित जगह के कारण यहाँ संसाधनों का अत्यंत ही अभाव है।

'आकाश' मिसाइल

ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम स्वदेशी तकनीक से युक्त 'आकाश' मिसाइल का आई.टी.आर. (एकीकृत टेस्ट रेंज) चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया। इसे डी.आर.डी.ओ. द्वारा तैयार किया गया है।

- इस मिसाइल को सेना में ज़मीन से हवा में कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल के तौर पर शामिल किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह पहली ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसमें रेडियो तरंगों के आधार पर अपने लक्ष्य को भेदने के लिये स्वदेशी तकनीक युक्त प्रणाली का प्रयोग किया गया है।
- इसके सफल परीक्षण के बाद भारत ने किसी भी तरह की ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल बनाने की क्षमता हासिल कर ली है।

मुख्य विशेषताएँ

- इसकी स्ट्राइक रेंज **25** किमी. है।
- वॉरहेड ले जाने की क्षमता **55** किलोग्राम है।
- इससे लो, मीडियम तथा हाई एलटीट्युड पर मौजूद टारगेट पर भी निशाना साधा जा सकता है।

आई.एस.ए. अब बना संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन

गिनी द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया है।

- आई.एस.ए. को भारत की पहल के बाद स्थापित किया गया था।
- इसकी शुरुआत पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा की गई थी।
- इस संगठन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
- साथ ही ऐसे देश जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मार्ग में अवस्थित हैं एवं सौर ऊर्जा के मामले में समृद्ध हैं, उनसे बेहतर तालमेल के ज़रिये सौर ऊर्जा की मांग पूरी करने हेतु बढ़ावा प्रदान करना है।
- आई.एस.ए. के समझौता प्रारूप पर अब तक **46** देशों द्वारा हस्ताक्षर किये जा चुके हैं, जबकि **20** देशों द्वारा अभी तक इसका अनुमोदन किया जा चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

- आई.एस.ए. के अंतरिम सचिवालय ने **25** जनवरी, **2016** से ही काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग, व्यापक स्तर पर किफायती ऋण, सौर मिनी ग्रिड की स्थापना, ये तीन कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं।
- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- उपरोक्त तीन मौजूदा कार्यक्रमों के अलावा आई.एस.ए. की योजना दो अन्य कार्यक्रमों को भी प्रारंभ करने की है। ये कार्यक्रम हैं-
  - ⇒ छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किये जाने को बढ़ावा देना।
  - ⇒ सौर ऊर्जा का भंडारण
  - ⇒ ई-गतिशीलता।

'इंटरनेट साथी' कार्यक्रम का होगा प्रसार

गूगल और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से भारत में जारी 'इंटरनेट साथी' कार्यक्रम का विस्तार होने जा रहा है। अब गूगल भारत की ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के साथ-साथ उन्हें इंटरनेट आधारित आजीविका अथवा रोज़गार उपलब्ध करवाने की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- गूगल इंडिया अब टाटा ट्रस्ट द्वारा निर्मित फाउंडेशन फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (फ्रेंड) के साथ मिलकर इंटरनेट साथी कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने पर काम करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- विभिन्न कंपनियाँ और संस्थान फ्रेंड के माध्यम से इंटरनेट साथी का प्रयोग सूचना और सेवाओं के प्रसार के लिये करेंगे।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट साथी की आय के नए अवसर पैदा होंगे।
- पूरे भारत में **12,000** से अधिक इंटरनेट साथी ने स्वेच्छा से अपने गाँवों में इंटरनेट साथी कार्यक्रम के इस अगले चरण में भाग लेने के लिये हस्ताक्षर किये हैं।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत **2015** में हुई और इसका उद्देश्य भारत की ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का 'स्वच्छ वायु के लिये संरक्षक' (UN Environment's Patron for Clean Air)

पे.टी.एम. के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के 'स्वच्छ वायु के लिये संरक्षक' का नाम दिया गया है। इसके पश्चात् वे न केवल उच्च पर्यावरणीय कार्रवाई करने और जागरूकता बढ़ाने में सहायता करेंगे, बल्कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के वैश्विक ब्रीथ लाइफ़ अभियान (UN Environment's global Breathe Life campaign) के लक्ष्यों हेतु अधिवक्ता की भूमिका का भी निर्वाहन करेंगे।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का वैश्विक ब्रीथ लाइफ अभियान लोगों के लिये बेहतर हवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये नीति निर्माण तथा नागरिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के संबंध में कार्य करेगा।

एक्सिस सिक्योरिटीज़ का NCDEX में पंजीकरण

एक्सिस बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज़, नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज (NCDEX) में पंजीकृत होकर कमोडिटी एक्सचेंज की सदस्यता लेने वाली कोई वित्तीय संस्था (बैंक) या उससे जुड़ी इकाई बन गई है।

- सितंबर माह में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अनुमति दी थी कि कमोडिटी बाज़ार में सहभागिता की इच्छा रखने वाले बैंक सेबी द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंडों का पालन करते हुए अपनी सहायक कंपनी स्थापित कर सकते हैं।
- किसी वित्तीय संस्थान (बैंक या उसकी सहायक कंपनी) के रूप में एक्सिस सिक्योरिटीज़ जैसी फर्मों के कमोडिटी ट्रेडिंग में शामिल होने से न केवल कमोडिटी एक्सचेंज की ट्रेडिंग का आधार बढ़ेगा, बल्कि कमोडिटी डेरीवेटिव ट्रेडिंग में निवेशकों का आत्मविश्वास और बढ़ने की संभावना है।

'उत्तरी ब्राउन कीवी' पक्षी अब लुप्तप्राय नहीं

हाल ही में आईयूसीएन (International Union for Conservation of Nature- IUCN) द्वारा जारी होने वाली रेड-लिस्ट में 'उत्तरी ब्राउन कीवी' पक्षी को लुप्तप्राय की श्रेणी से संवेदनशील जीवों की श्रेणी में डाल दिया गया है।

- कीवी की कुल **5** प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यह न्यूज़ीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है।
- कीवी, एपटरीगिडे परिवार (**Apterygidae family**) और एपट्रीक्स जेनस (**genus Apteryx**) से संबंध रखने वाला सबसे छोटा, न उड़ने वाला पक्षी है।
- इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान जंगलों के कटने और घातक कीटनाशकों के प्रयोग से हुआ है। इसीलिये बड़े पैमाने पर इनके संरक्षण के प्रयास किये जा रहे हैं।
- आधुनिक शोधों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि ये शुतुरमुर्ग (ऑस्ट्रिच) से सबसे निकटतम रूप से संबंधित हैं।
- दरअसल, कीवी के पंख तो होते हैं, लेकिन उनके शारीरिक ढाँचे में उन्हें सहारा देने वाली कोई भी

अस्थि नहीं होती, इसीलिये ये उड़ने में सक्षम नहीं होते।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आरोग्य, 2017

आयुष मंत्रालय और भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 'आरोग्य 2017' का आयोजन किया गया है, जिसमें फिक्की के साथ साझेदारी में फार्मेक्सिल (फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया - फार्मेक्सिल) सहित चिकित्सा प्रणाली की ताकत और वैज्ञानिक मूल्यांकन का प्रदर्शन किया गया है। वैकल्पिक चिकित्सा के 250 से अधिक निर्माताओं ने अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों के लिये अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया है।

- आयुष और तंदुरुस्ती पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन '**आरोग्य 2017**' का नई दिल्ली में आयोजन किया गया।
- आरोग्य **2017** का आयोजन फार्मेक्सिल सहित आयुष मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा फिक्की के साथ संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्देश्य औषधि की परंपरागत प्रणाली की ताकत और वैज्ञानिक मूल्यांकन को प्रदर्शित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- आरोग्य **2017** अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत में किया गया है। यह प्रदर्शनी और सम्मेलन आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा, होमियोपैथी और स्वास्थ्य पर आधारित है।
- आयुष मंत्रालय के ज़रिये भारत सरकार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर परंपरागत औषधि के विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, बल्कि अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर सहयोग के नए अवसरों का भी सृजन कर रही है।
- भारत आयुर्वेदिक और वैकल्पिक औषधि का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

भारतीय रेलवे स्टेशन विकास कार्पोरेशन लिमिटेड

हाल ही में रेलवे स्टेशन पुनर्विकास योजना के लिये भारतीय रेलवे स्टेशन विकास कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.आर.एस.डी.सी.) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

पृष्ठभूमि

- आई.आर.सी.ओएन. इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उपक्रम) और रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (**Rail Land Development Authority - RLDA)** के बीच एक संयुक्त उद्यम के तहत, आई.आर.एस.डी.सी. को विशेषज्ञों की एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप नियुक्त किया गया।
- इस रिपोर्ट में आई.आर.एस.डी.सी. की नियुक्ति एक त्वरित पुनर्विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई।

आई.आर.एस.डी.सी. क्या है?

- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, आई.आर.सी.ओ.एन. और आर.एल.डी.ए. (रेलवे मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
- आई.आर.एस.डी.सी. का मुख्य उद्देश्य विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों के निर्माण की परिकल्पना प्रस्तुत करना है, ताकि उपयोगकर्त्ताओं की सुविधा के अनुसार टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को लागू किया जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रहरी उपग्रह (Sentinel satellite)

प्रहरी - 5 पी, एक यूरोपीय उपग्रह है। इस उपग्रह द्वारा वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण की बढती दर के मापन संबंधी चित्र लिये जाते हैं। हाल ही में इस उपग्रह द्वारा भारतीय ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषण के चित्र एकत्रित किये गए हैं।

- इन चित्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वायु प्रदूषण के संबंध में सबसे खराब स्थिति उत्तर में बिहार के पटना से दक्षिण में छत्तीसगढ़ के रायपुर तक की है।
- प्रहरी- **5** पी उपग्रह को दैनिक स्तर पर वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों और कणों के वैश्विक मानचित्र बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **प्रहरी- 5 पी उपग्रह की विशेषता** प्रहरी **-5** पी उपग्रह यूरोपीय संघ (**European Union**) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (**European Space Agency**) द्वारा शुरू किये जाने वाले पृथ्वी पर्यवेक्षकों के बेड़े में सबसे नवीनतम अंतरिक्ष यान (**spacecraft**) है।

हरित पर्यावास (green habitat)

केरल सरकार पर्यावरण के अनुकूल तथा पुन: प्रयोज्य भवन निर्माण सामग्री, प्राकृतिक जल भंडारण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बल देने के लिये "हरित पर्यावास" की अवधारणा को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है।

"ग्रीन पर्यावास" की विशेषताएँ

- इस अवधारणा के तहत इमारतों को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करने की योजना बनाई गई है कि प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश और पवन का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
- इसका लाभ यह होगा कि बिजली का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा।
- इस प्रकार की इमारतों की एक अन्य प्रमुख विशेषता वर्षा जल संचयन या प्राकृतिक जल भंडारण प्रणाली होगी।
- इसके लिये सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि आम जनों के मध्य इसके प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिये तथा नीति-निर्माताओं द्वारा नीतियों, कार्यक्रमों इत्यादि की रूपरेखा तैयार करते समय इस अवधारणा को भी शामिल किया जाना चाहिये।

साइकॉन 2017

हाल ही में खेलकूद औषध एवं खेल विज्ञान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'साइकॉन' (Sports Medicine and Sports Sciences – SAICON) 2017 का उद्घाटन किया गया। खेलकूद औषध चिकित्सक तथा वैज्ञानिक एथलीटों के कार्य निष्पादन में विशेष योगदान देते हैं क्योंकि वह उनकी प्रतिभा तथा कौशल को निखारने का काम करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए 'खेलो भारत कार्यक्रम' के अंतर्गत खेलकूद विज्ञान का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- 'खेलो भारत कार्यक्रम' को स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर प्रतिभाओं की खोज करने के लिये तैयार किया गया है।
- 'खेलो भारत कार्यक्रम' के अंतर्गत, **17** वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिये अगले वर्ष **31** जनवरी से **8** फरवरी तक राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद आयोजित किये जाएंगे। इस बार पहली बार खेलकूद उद्घोषक द्वारा राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
- इस उत्सव में शीर्ष **1** हज़ार एथलीट **8** वर्ष के लिये **5** लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- मंत्रालय द्वारा हर वर्ष **1** हज़ार नए एथलीटों को इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि युवा प्रतिभाओं का एक पूल निर्मित किया जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सार्वजनिक खरीद पोर्टल 'एम.एस.एम.ई. संबंध'

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) द्वारा एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल 'एम.एस.एम.ई. संबंध' (MSME Sambandh) की शुरुआत की गई। इस पोर्टल का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एम.एस.एम.ई. से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।

- यह पोर्टल न केवल व्यवसाय को आसान बनाने का काम करेगा, बल्कि सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को भी बढ़ावा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (**PDS**), सरकार द्वारा प्रायोजित उचित मूल्य की दुकानों की श्रींखला है, जिनसे ज़रूरतमंद लोग आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, यह प्रणाली भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत, सामूहिक रूप से संचालित किया जाता है।

.सौर मंडल के अन्वेषण के लिये वर्चुअल संस्थान (Solar System Exploration Research Virtual Institute)

सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन रिसर्च वर्चुअल इंस्टिट्यूट, जिसका मूल नाम नासा चंद्र विज्ञान संस्थान (NASA Lunar Science Institute - NLSI) है, नासा द्वारा स्थापित एक संगठन है। यह नासा के चंद्र विज्ञान कार्यक्रमों को विस्तारित करने तथा इसके अनुपूरक के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख बिंदु

- नासा विज्ञान मिशन निदेशालय (**Science Mission Directorate - SMD)** और एक्सप्लोरेशन सिस्टम मिशन निदेशालय (**Exploration Systems Mission Directorate - ESMD)** द्वारा समर्थित एन.एल.एस.आई. को नासा एमेस रिसर्च सेंटर (**NASA Ames Research Center)** द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- यह नासा के एस्ट्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट (**NASA Astrobiology Institute - NAI)** पर आधारित संगठन है, जिसमें नासा के चंद्र अन्वेषण लक्ष्यों (**NASA's lunar exploration goals)** से संबंधित आयामों पर देश भर में फैले शोधकर्त्ताओं द्वारा एक साथ मिलकर काम किया जाता है।

अजेय योद्धा 2017 (Ajeya Warrior 2017)

'अजेय योद्धा' भारतीय सेना और रॉयल ब्रिटिश सेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। यह अभ्यास दो साल में एक बार (बारी-बारी से एक बार भारत में तथा एक बार ब्रिटेन में) आयोजित किया जाता है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस अभ्यास का उद्देश्य "भारतीय और ब्रिटेन की सेना के बीच सकारात्मक सैन्य संबंधों को स्थापित करना तथा बढ़ावा प्रदान करना है।

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank)

एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। इस बैंक की स्थापना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1966 में की गई थी, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है।

- इसके **67** सदस्य देश हैं।
- यह बैंक क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है।
- सामाजिक और पर्यावरण परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने पर बैंक का विशेष ध्यान रहता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख विशेषताएँ

- विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- आर्थिक विकास के लिये लोक एवं निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
- विकासशील सदस्य-राष्ट्रों की विकास योजनाओं और नीतियों के समन्वय में सहायता प्रदान करना।
- यह बैंक आधारभूत आर्थिक ढाँचे, शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिये धन सहायता प्रदान करता है।

एक नया पदार्थ 'एक्साइटोनियम'(excitonium)

वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के पदार्थ की खोज की है, जिसे 'एक्साइटोनियम' कहा जाता है। इसका सिद्धांत अब से लगभग 50 साल पहले हार्वर्ड के एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी बर्ट हैलपरिन (Bert Halperin) द्वारा दिया गया था।

- 'एक्साइटोनियम' एक सुपरकंडक्टर की तरह मैक्रोस्कोपिक क्वांटम घटना (**macroscopic quantum phenomena**) को दर्शाता है।
- यह एक्साइटोंस (**excitons**) कण से बना होता है, जो एक बहुत ही विचित्र क्वांटम मैकेनिकल युग्मन (**quantum mechanical pairing**) में बनते हैं।

हॉर्नबिल महोत्सव

'हॉर्नबिल महोत्सव' उत्तर-पूर्वी भारत के नागालैंड राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह सांस्कृतिक महोत्सव नृत्य, संगीत और भोजन के रूप में वर्षों से अपनाई गई नगा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है, जो कि नगा समाज की विविधताओं को प्रदर्शित करता है।

- इसे नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस (**1** दिसंबर, **1963**) के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है।
- प्रारंभ में इसे **7** दिनों के लिये आयोजित किया गया, किंतु इसकी बढ़ती सफलता, उपलब्धि एवं पर्यटन के मद्देनज़र, बाद में इसे **10** दिनों में परिवर्तित कर दिया गया।
- इस महोत्सव का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करने तथा इसकी सुरक्षा करने के साथ-साथ अपनी परंपराओं को प्रदर्शित करना है।

ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी (Great Hornbill)

- यह 'एनिमलीया किंगडम' के 'कॉर्डेटा समुदाय' के 'एवेस वर्ग' का एक पक्षी है, जिसे 'ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह मुख्य रूप से आर्द्र सदाबहार और मिश्रित पर्णपाती वनों में पाया जाता है।
- इसे **IUCN** की रेड डाटा बुक की **'Near Threatened'** सूची में रखा गया है।
- यह अरुणाचल प्रदेश तथा केरल राज्य का एक 'राजकीय पक्षी' **(State Bird)** भी है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

3D प्रिंटेड बायो इंक (Living materials' 3D-printed using bio ink)

वैज्ञानिकों द्वारा बैक्टीरिया-भारित स्याही (bacteria-loaded inks) का उपयोग करके तीन-आयामी (3D) 'जीवित पदार्थ' (living materials) को मुद्रित किया गया है। इस नए मुद्रित पदार्थ को "फंक्शनल लिविंग इंक" अथवा "फ्लिंक" (functional living ink – Flink) का नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह स्याही एक जैव-संगत हाइड्रोजेल से निर्मित है जो इसे संरचनात्मक रूप प्रदान करती है।
- इस हाइड्रोजेल को एक आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए शोधकर्त्ताओं ने "गुणों की श्रेणी" (**Range of Properties)** के साथ वांछित जीवाणुओं को संबद्ध किया**,** फिर उसकी सहायता से एक तीन-आयामी संरचना को प्रिंट किया गया।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (National Energy Conservation Day)

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency - BEE) ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्त्व के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिये प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (National Energy Conservation Day) के रूप में मनाया जाता है।

- जागरूकता फैलाने के रूप में बी.ई.ई. ऊर्जा उपभोग को कम करने में उद्योगों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करता है।
- इस अवसर पर "राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार" प्रदान किये जाते हैं।
- ये पुरस्कार भारत सरकार के विद्युत् मंत्रालय के तत्त्वावधान में ऊर्जा की महत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाले उपकरणों तथा प्रणालियों के उपयोग एवं संरक्षण के क्षेत्र में प्रदान किये जाते हैं।

दूसरा विश्व पर्यटन एवं संस्कृति सम्मेलन

11-12 दिसम्बर, 2017 को ओमान की राजधानी मस्कट में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन/ यूनेस्को द्वारा दूसरे विश्व पर्यटन व संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष इस सम्मेलन का मुख्य विषय "सतत् पोषणीय विकास" है।

सम्मेलन के अन्य मुख्य विषय हैं –

- शान्ति व समृद्धि के घटक के रूप में संस्कृति और पर्यटन का विकास।
- आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
- शहरी विकास व रचनात्मकता को सुनिश्चित करना।
- संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सांस्कृतिक स्थलों की पहचान करना।
- इन सबके अतिरिक्त, इस सम्मेलन में वर्ष **2030** के एस.डी.जी. के एजेंडे को प्राप्त करने पर भी बल दिया गया।

व्हाइट बीयर प्रॉब्लम (white bear problem)

मनोविज्ञान में व्हाइट बीयर प्रॉब्लम को विडंबना प्रक्रिया सिद्धांत (ironic process theory) के रूप में भी जाना जाता है। यह उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ विचारों को दबाने की प्रक्रिया उन विचारों के वास्तविक रूप में पुनः प्रकट होने का कारण बन सकती है।

- इसका अर्थ यह है कि किसी विचार को दबाना उससे छुटकारा पाने का कोई सचेत प्रयास साबित नहीं हो सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस सिद्धांत को इस प्रकार का नाम देना वाकई एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा, हालाँकि इसके नामकरण के संबंध में सफेद ध्रुवीय भालू के बारे में विचार नहीं किया गया।
- व्हाइट बीयर की समस्या के संबंध में सर्वप्रथम एक अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक डैनियल वेग्नर द्वारा वर्ष **1987** में अध्ययन किया गया।

नौसेना पनडुब्बी आई.एन.एस. कलवरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना की पनडुब्बी आई.एन.एस. कलवरी को राष्ट्र को समर्पित किया। आई.एन.एस. कलवरी एक डीज़ल - इलेक्ट्रिक युद्धक पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना के लिये मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है।

- इसका नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली टाइगर शार्क के नाम पर रखा गया है, जो एक बेहद आक्रामक समुद्री जीव होती है।
- यह उन **6** पनडुब्बियों में से पहली पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
- यह 'मेक इन इंडिया' पहल की कामयाबी को दर्शाती है। इस परियोजना को फ्रांँस के सहयोग से चलाया जा रहा है।

प्रमुख विशेषताएँ

- कलवरी एक ऐसी शक्तिशाली पनडुब्बी है जो समुद्री युद्ध के पूरे स्पेक्ट्रम में आक्रामक अभियान चला सकती है। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रतीक है।
- आत्म-रक्षा के संदर्भ में यह मोबाइल सी**303**/एस एंटी - टॉरपीडो डेकोस (**C303/S anti-torpedo decoys**) से युक्त है।
- इसके अतिरिक्त यह पनडुब्बी एक उच्च उन्नत लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली (**Highly advanced Combat Management System**) और एक परिष्कृत एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (**sophisticated Integrated Platform Management System**) का भी दावा प्रस्तुत करती है।

विश्व पर्यटन संगठन (World Tourism Organization)

विश्व पर्यटन संगठन (World Tourism Organization - UNWTO) संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो ज़िम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये उत्तरदायी है।

सदस्य

- यू.एन.डब्लू.टी.ओ. के सदस्य देशों में निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थानों, पर्यटन संगठनों और स्थानीय पर्यटन प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में **158** देश, **6** एसोसिएट सदस्य और **500** से अधिक संबद्ध सदस्य शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यू.एन.डब्लू.टी.ओ. न केवल आर्थिक विकास, समसामयिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के चालक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देता है, बल्कि साथ ही दुनिया भर में ज्ञान और पर्यटन नीतियों को आगे बढ़ाने हेतु इस क्षेत्र को नेतृत्व और समर्थन भी प्रदान करता है।
- वस्तुतः इसका उद्देश्य दुनिया भर में सतत् विकास को बढ़ावा देना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल, गोवा (Serendipity Arts Festival)

मंडोवी नदी (Mandovi river) के किनारे आयोजित होने वाला 'सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल' (Serendipity Arts Festival) एक ऐसा फेस्टिवल है, जहाँ दृश्य, प्रदर्शन और पाक कलाओं का एक साथ संगम होता है। इस फेस्टिवल का आयोजन दिसंबर माह में गोवा में किया जाता है।

- इसके अंतर्गत **40** से अधिक साधिकार परियोजनाएँ **(Commissioned projects)** संचालित की जाती हैं।
- कलाकारों के एक पैनल और संस्थागत आँकड़ों द्वारा तैयार की गई संरचना के आधार पर इस वर्ष का फेस्टिवल एक दीर्घकालिक सांस्कृतिक प्रोजेक्ट का पहला संस्करण होगा, जिससे एक बड़े पैमाने पर भारत में कलाओं में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद की जा रही है।
- सिर्फ एक भारतीय कला का प्रदर्शन होने के बजाय यह फेस्टिवल एक सांस्कृतिक प्रयोग (**cultural experiment)** है, जिसका समय के साथ भारतीय कलाओं पर गहरा असर होगा।
- जिस तरह से भारतीय अपने रोज़मर्रा के जीवन में विभिन्न कलाओं (शिक्षा, संरक्षण संस्कृति, अंतःविषय व्याख्यान इत्यादि) से रूबरू होते हैं, यह त्यौहार उन सभी को एक नए अंदाज़ में संबोधित करता है।

भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग

भारत जनवरी 2018 में होने वाली भारत-आसियान वार्ता में भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तारित करने के संबंध में बातचीत करने की योजना बना रहा है। भारतीय प्रस्ताव के अनुसार, लाओस और कंबोडिया के माध्यम से इस राजमार्ग को वियतनाम तक बढ़ाया जा सकता है।

- यदि इस राजमार्ग का विस्तार किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से इससे कनेक्टिविटी में भी विस्तार होगा।
- सड़क के माध्यम से दक्षिण-पूर्वी देशों के साथ भारत को जोड़ने की इस योजना से पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा फसलों के लिये बेहतर बाज़ार और रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- इससे न केवल किसानों को बल्कि उत्पादकों को भी अपने उत्पाद के लिये बेहतर मूल्य प्राप्त होगा, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।

आई.एम.टी. राजमार्ग

- भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत आने वाला एक राजमार्ग है। इस राजमार्ग से आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के बाकी हिस्सों में भी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

लंदन गोल्ड पूल (London gold pool)

यह ब्रेटन वुड्स मौद्रिक प्रणाली (Bretton Woods monetary system) को अपनाने के लिये आठ केंद्रीय बैंकों द्वारा बनाए गए सोने के भंडार के पूल को संदर्भित करता है। जब कभी भी बाज़ार में सोने की कीमत $35 से ऊपर जाने लगती है, तब बैंकों द्वारा लंदन के खुले बाज़ार में अतिरिक्त सोने का प्रवाह बढ़ा दिया जाता है।

- ब्रेटन वुड्स के तहत, विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं के धारकों को **$ 35** की निश्चित कीमत पर एक औंस सोने का हकदार माना गया। इसलिये यह बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया कि सोने के बाज़ार मूल्य को **$ 35** पर निश्चित किया जाए।
- अन्यथा, इसके परिणामस्वरूप उन दलों की ऋणमुक्ति संबंधी मांग में इज़ाफा हो जाएगा, जो इस निश्चित मांग में कमी करते हुए उच्च कीमत पर बाज़ार में सोने को बेचने का प्रयास करेंगे।
- ब्रेटन वुड्स के तहत निम्नलिखित राष्ट्रीय मुद्रा धारक देशों को शामिल किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ संयुक्त राज्य अमेरिका
- ✓ जर्मनी
- ✓ यूनाइटेड किंगडम
- ✓ फ्राँस
- ✓ इटली
- ✓ बेल्ज़ियम
- ✓ नीदरलैंड
- ✓ स्विट्ज़रलैंड

पैलेडियम (Palladium)

पैलेडियम एक चमकीली धातु है, जिसे रासायनिक सूत्र pd के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। इस धातु को प्लैटिनम समूह में शामिल एस्ट्रोयड पलास के नाम पर यह नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

यह प्लैटिनम की भाँति चमकीला एवं हल्का होता है।

- इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होता है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक, मेडिसन, आभूषण इत्यदि में किया जाता है।
- इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण इसे उत्प्रेरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
- इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि यह वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुएँ (हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन आदि) को कम नुकसानदायक कणों में परिवर्तित करने में भी सक्षम होता है।
- इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में एग्जोस्ट से निकलने वाला धुँआ नाइट्रोजन, कार्बन तथा भाप में परिवर्तित हो जाता है।

कॉकलियर इम्प्लांट Cochlear implant

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संगठनों, सार्वजनिक और कॉरपोरेट क्षेत्रों का आह्वान करते हुए दिव्यांगजनों की सहायता के लिये कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पूरा करने हेतु आगे आने की अपील की गई है। एक आकलन के अनुसार, देश में लगभग ऐसे 35 हज़ार बच्चे हैं, जिन्हें हर वर्ष कॉकलियर इम्प्लांट की आवश्यकता होती है।

कॉकलियर इम्प्लांट क्या है ?

- यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जिसके दो भाग (बाहरी और अंदरूनी) होते हैं।
- अंदरूनी भाग ई.एन.टी. चिकित्सक (कान, नाक और गले से संबंधित चिकित्सक) ऑपरेशन के ज़रिये सिर के भीतर लगा देते हैं। इस ऑपरेशन के बाद विशेषज्ञ और प्रशिक्षक लोग व्यक्ति को सुनने और बोलने का प्रशिक्षण देते हैं।
- इस पूरी प्रक्रिया में माता-पिता की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि घर पर बच्चे को भाषा को सीखने, सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करने में उनका योगदान अत्यंत अहम होता है।
- ए.डी.आई.पी. योजना के तहत **1** साल से **5** साल की आयु के बच्चे कॉकलियर इम्प्लांट के लिये पात्र होते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

कॉकलियर इंप्लांट तकनीक से इन बच्चों को मदद मिलती है-

- जो बच्चे दोनों कानों में गंभीर बधिरता से पीड़ित हों।
- जिन्हें हियरिंग एड से अत्यंत कम या कोई लाभ न हो।
- जो मानसिक रूप से अक्षम न हों या जिनके शारीरिक–मानसिक विकास में कोई खामी न हो।

पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढाँचा विकास योजना North East Special Infrastructure Development Scheme

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 90:10 की निधियन पद्धति वाली मौजूदा नॉन लेप्सेबल सेन्ट्रल पूल ऑफ रिर्सोसेज (Non Lapsable Central Pool of Resources - NLCPR) योजना को 5300.00 करोड़ रुपए के खर्च के साथ मार्च 2020 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को पूरा करना है।

एन.ई.एस.आई.डी.एस. की विशेषताएँ

इस नई योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे के सृजन को शामिल किया गया है:

- जलापूर्ति, विद्युत, संपर्क और विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित भौतिक बुनियादी ढाँचा।
- शिक्षा और स्वास्थ्य के सामाजिक क्षेत्रों का बुनियादी ढाँचा।

सामुद्रिक विज्ञान के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र International Training Centre for Operational Oceanography

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीयमंत्रिमंडल ने यूनेस्को के श्रेणी-2 केंद्र (Category-2 Centre (C2C) के रूप में हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (International Training Centre for Operational Oceanography) स्थापित करने को मंज़ूरी दी है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य हिंद महासागर के किनारों (**Indian Ocean Rim - IOR**), भारतीय और अटलांटिक महासागर से जुड़े अफ्रीकी देशों, यूनेस्को के ढाँचे के अंतर्गत, लघु द्वीपीय देशों के लिये क्षमता निर्माण की दिशा में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान मछुआरों, आपदा प्रबंधन, ज़हाजरानी, बंदरगाह, तटीय राज्यों, नौसेना, तट रक्षक, पर्यावरण, दैनिक परिचालन को सुचारु रूप से चलाने के लिये अपतटीय उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों को सूचनाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक कारगर गतिविधि है।
- यह भारत को हिंद महासागर की सीमाओं से जुड़े दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों सहित इसके अंतर्गत आने वाले अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और रिश्तों को सुधारने में भी मदद करेगा।

लाइटकॉइन (Litecoin)

डिजिटल करेंसी लाइटकॉइन आई.ओ.टी.ए. (IOTA) और रिप्पल (Ripple) को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई है। हालाँकि बाज़ारी पूंजीकरण के मामले में अभी भी बिटकॉइन ही नंबर एक पर कायम है।

प्रमुख बिंदु

- दूसरे एवं तीसरे नंबर पर एथरियम (**Ethereum**) एवं बिटकॉइन कैश कायम है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आई.ओ.टी.ए. (IOTA)

आई.ओ.टी.ए. एक मुक्त स्रोत वितरित खात क्रिप्टोकरेंसी (open-source distributed ledger (cryptocurrency) है। यह आई.ओ.टी. (Internet of Things) पर सुरक्षित संचार और मशीनों के बीच भुगतान प्रदान पर केंद्रित क्रिप्टोकरेंसी है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अंतर्गत पारंपरिक ब्लॉकचेन **(blockchain)** के बजाय निर्देशित एसाइक्लिक ग्राफ (**directed acyclic graph - DAG)** तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
- इसके तहत लेन-देन के आकार की परवाह किये बिना आई.ओ.टी.ए. का नि:शुल्क लेन-देन किया जाता है।
- लेन-देन की पुष्टि का समय काफी तीव्र है, यह एक साथ असीमित संख्या में लेन-देन को व्यवस्थित कर सकता है, साथ ही इस सिस्टम को आसानी से मापा भी जा सकता है।

रिप्पल (Ripple)

रिप्पल (Ripple - XRP) एक पीयर-टू-पीयर समर्थित क्रिप्टोकरेंसी (peer-to-peer powered cryptocurrency) है, जिसे वेब के संबंध में सुरक्षित, तीव्र एवं प्रत्यक्ष भुगतान करने के लिये तैयार किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह आर.टी.जी.एस (**real time gross settlements (RTGS),** मुद्रा विनिमय और मनी ट्रांसफर की एक प्रणाली है।
- इसका एक अन्य नाम रिप्पल ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल (**Ripple transaction protocol (RTXP)** या रिप्पल प्रोटोकॉल (**Ripple protocol)** है।

एथरियम (Ethereum)

एथरियम (Ethereum) एक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक खुला सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो डेवलपर को विकेंद्रित अनुप्रयोगों को तैयार करने तथा लागू करने में सक्षम बनाता है।

प्रमुख बिंदु

- बिटकॉइन की तरह एथरियम भी एक वितरित सार्वजनिक ब्लॉकचेन नेटवर्क है।
- हालाँकि, इन दोनों के बीच कुछ महत्त्वपूर्ण तकनीकी मतभेद भी हैं, इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि बिटकॉइन और एथरियम के उद्देश्य और क्षमता में काफी भिन्नता है।

न्याय ग्राम परियोजना Nyaya Gram project

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आवासीय और प्रशिक्षण परिसर में 'न्याय ग्राम' परियोजना की आधारशिला रखी गई।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- यह परियोजना इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की एक मॉडल टाउनशिप है। इस टाउनशिप में एक न्यायिक अकादमी तथा एक सभागार की व्यवस्था की गई है।
- इसके अतिरिक्त, इसके अंतर्गत न्यायाधीशों तथा कर्मचारियों के लिये आवास की भी व्यवस्था की गई है।
- इस परियोजना का उद्देश्य किसी भी प्रकार से न्याय व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले कारकों का समाधान करना है।

सेंडाई फ्रेमवर्क Sendai Framework

वर्ष 2015 में सेंडाई, जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में 187 देशों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) को अपनाया गया था।

सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है?

- सेंडाई फ्रेमवर्क एक प्रगतिशील फ्रेमवर्क है और इस महत्त्वपूर्ण फ्रेमवर्क का उद्देश्य **2030** तक आपदाओं के कारण होने वाले महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने वाला भारत पहला देश है।

उद्देश्य

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निर्मित सेंडाई फ्रेमवर्क का उद्देश्य आपदा के संदर्भ में प्रबंधन की रणनीति का अनुपालन करना है।
- यह फ्रेमवर्क छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सभी प्रकार की आपदाओं, प्राकृतिक एवं मानव जनित खतरों, पर्यावरणीय, तकनीकी आदि खतरों के संबंध में लागू होगा।

लक्ष्य

- वर्ष **2030** तक वैश्विक जीडीपी में प्रत्यक्ष आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना।
- वर्ष **2030** तक विभिन्न प्रकार के खतरों के संबंध में पूर्व-चेतावनी प्रणाली उपलब्ध कराना।
- वर्ष **2030** तक राष्ट्रीय एवं स्थानीय आपदा जोखिम में कमी की रणनीतियाँ तैयार करना, साथ ही इस कार्य के लिये अधिक से अधिक देशों को सहयोग प्रदान करना।
- वर्ष **2030** तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर में कमी लाना।

ट्यूरिअल जलविद्युत ऊर्जा परियोजना Tuirial Hydro Electric Power Project (HEPP)

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिज़ोरम में 60 मेगावॉट की ट्यूरिअल जलविद्युत ऊर्जा परियोजना (Tuirial Hydro Electric Power Project - HEPP) को राष्ट्र को समर्पित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- ट्यूरिअल जलविद्युत ऊर्जा परियोजना का निर्माण केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसका क्रियान्वयन विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (**North Eastern Electric Power Corporation - NEEPCO)** द्वारा किया गया है।
- यह परियोजना मिज़ोरम में स्थापित सबसे बड़ी परियोजना है और इससे उत्पादित बिजली राज्य को दी जाएगी।

लाभ

- इससे राज्य का संपूर्ण विकास और केंद्र सरकार के महत्त्वाकांक्षी और प्रमुख कार्यक्रम "सभी को सातों दिन चौबीसों घंटे किफायती स्वच्छ ऊर्जा" के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकेगा।
- परियोजना से अतिरिक्त **60** मेगावाट बिजली प्राप्त होने के साथ ही मिज़ोरम राज्य अब सिक्किम और त्रिपुरा के बाद पूर्वोत्तर भारत का तीसरा विद्युत-अधिशेष राज्य बन जाएगा।

भारतमाला सड़क परियोजना

केंद्र सरकार द्वारा सभी मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को भारतमाला के तहत लाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बाद भारतमाला दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में लगभग **50,000** किमी. सड़कों का विकास हुआ, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज भी शामिल है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर को सिलचर से जोड़ती है।
- भारतमाला के तहत, बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें सीमा क्षेत्रों में सड़कों का नेटवर्क बिछाया जाना भी शामिल है।

सागरमाला परियोजना

केंद्र सरकार द्वारा बंदरगाहों के विकास के लिये सागरमाला परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ बढ़ते आर्थिक विकास की राह को भी गति प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु

- सागरमाला केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश में बंदरगाहों की अगुवाई में विकास की गति तेज़ करना है।
- यह न्यूनतम निवेश के साथ निर्यात-आयात एवं घरेलू व्यापार की लागत काफी हद तक कम करने संबंधी सागरमाला के विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- जल परिवहन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी करने में मदद मिलेगी, जो चीन एवं यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में बहुत अधिक है।

उद्देश्य

- सागरमाला परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों के आस-पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना।
- मुख्य मंडियों तक संपर्क सुधारना व रेल, अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय एवं सड़क सेवाओं में सुधार करना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पीज़ोइलेक्ट्रिक सामग्री से उत्पन्न ऊर्जा

आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने कचरा प्याज की त्वचा का इस्तेमाल करते हुए एक सस्ती डिवाइस विकसित की है जो शारीरिक गतिविधियों से हरित बिजली **('green' electricity)** पैदा कर सकती है, साथ ही पेसमेकर्स **(pacemakers)**, स्मार्ट गोलियों **(smart pills)** और पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स **(wearable electronics)** को चार्ज भी कर सकती है।

प्रमुख बिंदु

- जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद इन पर बढ़ते बोझ तथा वर्तमान समय में ऊर्जा की कमी ने दुनिया में टिकाऊ और वैकल्पिक हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकल्प के संबंध में गंभीरता से विचार करने को विवश कर दिया है।
- हालाँकि, पीज़ोइलेक्ट्रिक नैनो-जनरेटर्स **(piezoelectric nano-generators)** को संश्लेषित करना एक बेहद कठिन और महँगा कार्य है।
- साथ ही, ये आमतौर पर अत्यधिक ज़हरीले होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वास्तविक जीवन में इनका उपयोग सीमित मात्रा में ही किया जाता है।

नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017(National Health Policy – NHP)

सरकार द्वारा वर्ष 2017 में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई। इस नीति के तहत बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थितियों और उभर रही चुनौतियों का समाधान किया गया है।

- एन.एच.पी. **2017** का प्रमुख संकल्प **2025** तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जी.डी.पी. के **2.5** प्रतिशत तक बढ़ाना है।

प्रमुख बिंदु

- एन.एच.पी. **2017** में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराने और प्रति एक हज़ार की आबादी पर दो बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर बल देता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रमुख आकर्षण निम्नलिखित हैं:

- **पोषक तत्वों की कमी-** पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्वों की पर्याप्तता में विविधता पर फोकस।
- **देखभाल गुणवत्ता-** सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें गुणवत्ता स्तर का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- **मेक इन इंडिया पहल-** नीति में दीर्घकालिक दृष्टि से भारतीय आबादी के लिये देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल।
- **डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली-**स्वास्थ्य नीति में चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिये डिजिटल उपायों की व्यापक तैनाती पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.)

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों के तहत राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य कुपोषण के अंतर-पीढ़ी चक्र को रोकने के लिये जीवन-चक्र दृष्टिकोण को अपनाना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- मिशन के तहत, वृद्धि स्तर को कम करने, कुपोषण, एनीमिया तथा कम वज़न के नवजातों की संख्या में कमी लाने की परिकल्पना की गई है। मिशन का उद्देश्य **10** करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करना है।

मिशन के प्रमुख घटक/विशेषताएँ

- कुपोषण से निपटने में योगदान करने वाली विभिन्न योजनाओं का मानचित्रण।
- आपसी मिलन की सुदृढ़ व्यवस्था लागू करना।
- आईसीटी आधारित रियल टाइम निगरानी प्रणाली।
- लक्ष्यों की पूर्ति के लिये राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों को संवेदी बनाना।

नए टीके का परिचय

निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) (Inactivated polio vaccine (IPV)

- भारत पोलियो मुक्त देश है, लेकिन इस स्थिति को बनाए रखने के लिये निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) पेश किया गया, जिसके तहत अक्टूबर, **2017** तक देश में आईपीवी की **2.95** करोड़ दवा खुराकों की व्यवस्था की गई।

वयस्क (एडल्ट) जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) वैक्सीन (Japanese Encephalitis (JE vaccine)

जापानी एन्सेफलाइटिस 15 साल से कम उम्र के बच्चों में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला प्राणघातक वायरल रोग है। यह विषाणुजन्य रोग 'Japanese Encephalitis Virus' (जो कि एक flavivirus है) के कारण होता है। सामान्यतया यह रोग 'Japanese Encephalitis Virus' से संक्रमित मच्छरों (मुख्य रूप से क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों) के काटने से फैलता है।

- इसके संक्रमण से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में तनाव, दौरा पड़ना व कोमा जैसी स्थिति बन सकती है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली वयस्कों की तुलना में काफी कमज़ोर होती है।
- 'मिशन इन्द्रधनुष' के अंतर्गत मुख्य रूप से **7** बीमारियों को समाप्त करने हेतु टीके की व्यवस्था की गई है। किंतु, देश के कुछ चयनित राज्यों में जे.ई. तथा एच.आई.वी. के लिये भी टीके की व्यवस्था कराई गई है।
- इस संदर्भ में राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम (एनवीबीडीसीपी) के तहत, वयस्क जेई टीकाकरण के लिये असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के **31** प्रभावित ज़िलों की भी पहचान (**15- 65** साल के आयु समूह में) की गई।
- वयस्क जेई टीकाकरण अभियान असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के सभी **31** ज़िलों में पूरा किया गया है, जिसमें **15-65** वर्ष की आयु के **3.3** करोड़ लाभार्थियों को टीके लगाए गए हैं।

रोटावायरस वैक्सीन (rotavirus vaccine)

रोटावायरस एक प्रकार का संक्रमण है जो अतिसार का बिगड़ा हुआ रूप होता है और ठंड में अधिकतर बच्चों में फैलता है। यदि एक बच्चे को इसका संक्रमण हो जाए, तो उसके संपर्क में रहने से दूसरे बच्चे को भी हो सकता है। यह विशेषकर गंदगी के कारण होता है।

- इसका संक्रमण होने पर बच्चे को अतिसार तथा उल्टियाँ होने लगती हैं और यह सामान्य डायरिया से अधिक खतरनाक होता है।
- अतिसार और उल्टियों के कारण बच्चों में निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) तक हो जाता है।
- रोटावायरस से होने वाला यह संक्रमण नवजात शिशु से लेकर पाँच साल तक के बच्चों में अधिक होता है। रोटावायरस युवा बच्चों के बीच गंभीर दस्त के कारण मौत के प्रमुख कारणों में से एक है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- फिलहाल **9** राज्यों – आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा में रोटावायरस टीका पेश किया गया है।

खसरा-रुबेला (एम.आर) वैक्सीन (measles-rubella (MR) vaccine)

रुबेला को "जर्मन खसरा" के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी रुबेला वायरस के कारण होती है। यह संक्रमित व्यक्ति की नाक और ग्रसनी से स्राव की बूँदों से या फिर सीधे रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है।

- रुबेला संक्रमण के कारण जन्मजात दोषों के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिये रुबेला वैक्सीन को खसरा-रुबेला वैक्सीन के रूप में यूआईपी में पेश किया गया है। चरणबद्ध तरीके से एमआर अभियान को शुरू किया जा रहा है। हालाँकि, यह **5** राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों (कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी) में फरवरी, **2017** से शुरू किया गया था।
- इन राज्यों और संघ-शासित प्रदेशों में **9-12** महीने और **16-24** महीनों में दो खुराक के रूप में नियमित टीकाकरण में एमआर टीका पेश किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम के अंतर्गत, देश में मानसिक स्वास्थ्य सुधार हेतु आधार आधारित वैधानिक ढाँचा अपनाए जाने पर बल दिया गया है।

- यह अधिनियम स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण तथा उचित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये संस्थागत व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सरकारी और निजी क्षेत्रों के दायित्व को भी सुनिश्चित करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व शामिल है।

एन.सी.डी. के फ्लेक्सी पूल (flexi pool) में मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम

- मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गैर-संचारी रोगों (**non-communicable diseases - NCDs)** के फ्लेक्सी पूल (**flexi pool)** के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- एन.सी.डी. के फ्लेक्सी पूल (**flexi pool)** हेतु आवंटित राशि को पिछले दो वर्षों में तकरीबन तीन गुना बढ़ाया गया है। यानी अब राज्यों द्वारा केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के कोष का उपयोग विशेषज्ञों एवं अन्य सुविधाओं के भुगतान में किया जा सकता है।

"लक्ष्य"- प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल

माँ एवं नवजात शिशुओं की उच्च मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से शिशुओं के जन्म के समय प्रसव कक्षों में देखभाल की बेहतर गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था स्थापित करना अत्यंत ज़रूरी होता है, ताकि माँ एवं नवजात शिशु दोनों के ही जीवन को कोई खतरा न हो।

- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'लक्ष्य'- प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल की शुरुआत की गई है। 'लक्ष्य' के माध्यम से प्रसव कक्षों और ऑपरेशन थियेटर में गर्भवती माँ की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सकती है।
- इसके साथ-साथ यह नवजात शिशुओं के जन्म के समय उत्पन्न होने वाली अवांछनीय प्रतिकूल स्थितियों से भी सुरक्षा प्रदान करेगी।
- यह पहल सरकारी मेडिकल कॉलजों के अलावा ज़िला अस्पतालों (**District Hospitals - DHs),** अधिक डिलीवरी लोड वाले उप-ज़िला अस्पतालों (**Sub-District Hospitals – SDHs)** और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (**Community Health Centres – CHCs)** में भी प्रभावी होगी.

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फरवरी 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के 27 करोड़ से भी अधिक बच्चों में चार प्रकार की परेशानियों की जाँच करना है, जिनमें जन्म के समय किसी प्रकार के विकार, बीमारी, कमी और विकलांगता सहित विकास में रुकावट की जाँच शामिल है।

ज़िला शुरुआती जाँच केंद्र (डीईआईसी)

- ज़िला अस्पताल में एक शुरुआती जाँच केंद्र (अर्ली इंटरवेंशन सेंटर) खोला जाएगा। इस केंद्र का उद्देश्य स्वास्थ्य जाँच के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले बच्चों को रेफरल सहायता उपलब्ध कराना है।
- इसकी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये शिशु चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्सों, पैराचिकित्सक वाले एक दल की नियुक्ति की जाएगी।
- इसके तहत एक प्रबंधक की नियुक्ति का भी प्रावधान है जो पर्याप्त रेफरल सहायता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पता लगाएगा।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके)

- **2014** में एक व्यापक कार्यक्रम के तहत यौन प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, चोट लगने और हिंसा (लिंग आधारित हिंसा सहित) पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- स्वास्थ्य सुविधाओं, समुदाय और स्कूलों को प्लेटफॉर्म के रूप में हस्तक्षेप के लिये इस्तेमाल किया जाता है।

किशोरावस्था के अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक

- ये किशोरों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के संपर्क के पहले स्तर के रूप में कार्य करते हैं। ।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन (वाईफ) प्रोग्राम

- इसमें स्कूली लड़कों और लड़कियों के लिये साप्ताहिक पर्यवेक्षण आईएफए गोलियों का प्रावधान और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा दो वर्षीय बच्चों और दो वर्षीय अल्बेन्डाजोल की गोलियाँ शामिल हैं।

मासिक धर्म स्वच्छता योजना

- यह योजना ग्रामीण इलाकों में किशोरियों के लिये लागू की जा रही है। सेनेटरी नैपकिन की खरीद को वर्ष **2014** से विकेंद्रीकृत किया गया है।

पीयर एजुकेशन प्रोग्राम

- इस कार्यक्रम के तहत चार पीयर एडुकेटर्स (साथी) - स्वास्थ्य समस्याओं पर किशोरों को जानकारी देने के लिये प्रति **1000** आबादी के लिये दो पुरुष और दो महिलाओं का चयन किया जाता है।
- पीयर एजुकेशन प्रोग्राम को **211** ज़िलों में लागू किया जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

मिशन परिवार विकास

11 जुलाई, 2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण के लिये देश के 7 राज्यों के 146 ज़िलों में एक परिवार नियोजन कार्यक्रम "मिशन परिवार विकास" शुरू किया गया।

- इस पहल के तहत परिवार नियोजन हेतु आवश्यक दवाओं को मुहैया करने, प्रमोशनल स्कीम शुरू करने, क्षमता बढ़ाने, सुलभ वातावरण तैयार करने तथा गहन निगरानी के ज़रिये बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा।
- इसके साथ-साथ मंत्रालय द्वारा "अंतरा" कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिये नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन तथा हार्मोन रहित सेंट्रोकोमन गोली "छाया" की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों की ग्राह्यता बढ़ाने पर भी बल दिया गया।

अमृत (उपचार के लिये उचित मेडिकल और विश्वसनीय प्रत्यायोजन)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रोगियों के लिये रियायती कीमतों पर मधुमेह, सी.वी.डी., कैंसर और अन्य रोगों हेतु दवाएँ उपलब्ध कराने के लिये **19** राज्यों में **105** फार्मेसियों की स्थापना की गई है।
- इन फार्मेसियों में **5000** से अधिक दवाओं और अन्य उपभोग्य वस्तुओं को **50%** की छूट पर बेचा जा रहा है।

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली

- फीस और नियुक्ति, ऑनलाइन निदान रिपोर्ट, रक्त आदि की ऑनलाइन उपलब्धता के विषय में पूछताछ के लिये विभिन्न अस्पतालों को लिंक करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की एक रूपरेखा तैयार की गई है।

ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली electronic-Human Resource Management System (e-HRMS)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस) का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली के पाँच मॉड्यूलों के अंतर्गत 25 एप्स आरंभ किये गए।

प्रमुख बिंदु

- **30** मार्च, **2017** से पहले जारी ई-सेवा पुस्तिका को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा।
- कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के बाद ये मॉड्यूल अगले महीने तक पूरी तरह कार्य करने लगेंगे और शेष मॉड्यूल इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक विकसित कर लिये जाएंगे।

उद्देश्य

- यह संपूर्ण स्वचालित मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली की दिशा में एक अहम् कदम है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के सभी कर्मचारियों को कार्मिक पोर्टल पर लाना है, ताकि तैनाती से लेकर सेवानिवृत्त होने तक कार्मिक प्रबंधन की सभी प्रक्रियाएँ डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो सकें तथा कार्मिक प्रबंधन की हस्तचालित प्रणाली को इसके साथ संबद्ध किया जा सके।

राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्द्धन प्रकोष्ठ National Highways Investment Promotion Cell (NHIPC)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग परियोजनाओं के लिये घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु एक राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्द्धन प्रकोष्ठ (एन.एच.आई.पी.सी.) गठित किया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- यह प्रकोष्ठ सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक संस्थागत निवेशकों, निर्माण कंपनियों, डेवलपरों और कोष प्रबंधकों के साथ सहभागिता पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा।
- एनएचआईपीसी मुख्य रूप से सड़क से जुड़े बुनियादी ढाँचे या अवसंरचना में विदेशी एवं घरेलू निवेश को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' भारत सरकार के 'रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय' के अंतर्गत कार्यरत 'फार्मास्यूटिकल्स विभाग' द्वारा प्रारंभ की गई है।
- इसका उद्देश्य 'प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र' के माध्यम से देश की जनता को सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ प्रदान करना है।
- इन जन औषधि केन्द्रों को गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता में महँगी ब्रांडेड दवाओं के समतुल्य जेनेरिक दवाइयों को कम कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिये स्थापित किया गया है।
- इस परियोजना का मूल उद्देश्य है- **"Quality Medicines at Affordable Prices for All"**।

समीप कार्यक्रम (SAMEEP)

भारतीय विदेश नीति को आम लोगों तक पहुँचाने के लिये भारतीय विदेश मंत्रालय ने 'समीप' (SAMEEP) नामक पहल लॉन्च की है। इसका पूरा नाम 'छात्र और विदेश मंत्रालय सहभागिता कार्यक्रम' (Students and MEA Engagement Programme-SAMEEP) है।

प्रमुख बिंदु

- इस 'छात्र और विदेश मंत्रालय सहभागिता कार्यक्रम' का मुख्य उद्देश्य भारत की विदेश नीति और वैश्विक गतिविधियों से छात्रों को अवगत कराना है।
- 'समीप' का संचालन आउटरीच मिशन की तरह किया जाएगा।
- कार्यक्रम का एजेंडा न सिर्फ छात्रों को विश्व में भारत के स्थान और इसकी वैश्विक महत्त्वाकांक्षाओं के बारे में जागरूक करना है, बल्कि कैरियर विकल्प के रूप में कूटनीति में रुचि बढ़ाना भी है।
- अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा एक बुनियादी मानकीकृत प्रस्तुति प्रदान की जाएगी, लेकिन अपने स्वयं के अनुभवों और सुधारों को इसमें जोड़ने के लिये वे स्वतंत्र होंगे।
- इस पहल का 'समीप' नाम **mygov.in** पर आए सुझावों के आधार पर रखा गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर 'प्रवक्ता से पूछो' **(Ask the Spokesperson)** नामक इंटरैक्टिव कार्यक्रम के तहत, भारत की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है।

सीखो और कमाओ

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं के कौशल विकास हेतु कई विशेष योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं।

- "सीखो और कमाओ" नियोजन से जुड़े अल्पसंख्यकों हेतु लाई गई कौशल विकास योजना है, जिसका उद्देश्य विभिन्न आधुनिक/परंपरागत कौशलों में अल्पसंख्यक युवाओं को उन्नयित करना है जो उनकी अर्हता, मौजूदा आर्थिक प्रवाह तथा बाज़ार संभावनाओं पर निर्भर करते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसका उद्देश्य इन युवाओं को उपयुक्त रोज़गार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ स्वरोज़गार के लिये अच्छी तरह कुशल बनाना है।

बालश्रम के खात्मे हेतु पेंसिल पोर्टल Launching of Pencil Portal to Eliminate Child Labour

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल (PENCIL - Platform for Effective Enforcement for No Child Labour) विकसित किया गया है, जिसे 26 सितंबर, 2017 को शुरू किया गया था।

पेंसिल पोर्टल के मुख्य घटक

- बाल एवं किशोर श्रम ट्रैकिंग प्रणाली (**child & adolescent labour tracking system)**
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (**Ministry of Labour & Employment)** से संबद्ध एन.सी.एल.पी. और राज्य संसाधन केंद्र (**NCLP and State Resource Centre)** की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा, इस पोर्टल पर प्राप्त आँकड़ों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (**Ministry of Women & Child Development),** मानव संसाधन विकास मंत्रालय (**Ministry of Human Resource Development)** और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (**Ministry of Skill Development & Entrepreneurship)** के साथ साझा किया जाएगा।
- राज्य सरकार के स्तर पर इसकी निगरानी राज्य श्रम विभाग में स्थापित राज्य संसाधन केंद्र द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त ज़िला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी (**District Nodal Officers - DNOs)** को उनसे संबंधित ज़िलों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिये नामित किया गया है।

चीन द्वारा अपने पहले स्वदेशी फोटोवोल्टिक हाईवे का सफल परीक्षण

हाल ही में चीन ने देश के पूर्वी शेडोंग प्रांत में स्वदेशी तकनीक पर आधारित अपने पहले **'फोटोवोल्टिक राजमार्ग' (Photovoltaic Highway)** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस राजमार्ग को सौर पैनलों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस राजमार्ग को सौर पैनलों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। इनके ऊपर कंक्रीट की एक पतली चादर है, जो एक सुरक्षात्मक सतह के रूप में कार्य करती है। ये पैनल, इन पर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेंगे।
- इस राजमार्ग पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिये वायरलेस चार्जिंग की सुविधा के साथ ही ड्रोन्स के लिये सेंसर भी उपलब्ध रहेंगे। इन पैनलों पर संचित सौर ऊर्जा का उपयोग सर्दी में सड़क पर जमी बर्फ पिघलाने में भी किया जा सकेगा।
- चीन के पूर्वी शहर हैनान (**Huainan)** में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है।
- दुनिया का पहला सोलर पैनल युक्त फोटोवोल्टिक राजमार्ग **2016** में फ्राँस में खोला गया था। चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश है।
- फोटोवोल्टिक सेल (पीवी सेल) एक विशेष प्रकार की अर्द्धचालक युक्ति है जो, दृश्यमान प्रकाश (**Visible Light)** को प्रत्यक्ष धारा (**Direct Current-DC)** में बदल देती है। कुछ पीवी सेल्स अवरक्त (**Infrared)** या पराबैंगनी (**Ultraviolet)** विकिरण को भी प्रत्यक्ष धारा में रूपांतरित कर सकते हैं। फोटोवोल्टिक सेल सौर-विद्युत ऊर्जा प्रणालियों का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जिनका वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में उपयोग तेज़ी से बढ़ता जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत और विश्व

वर्ष 2020 तक भारत में 50% मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रयास

भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, भारत में मलेरिया के मामलों में एक तिहाई की कमी दर्ज की गई है।

'दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन' बैठक का आयोजन

- हाल ही में मलेरिया पर नियंत्रण और उन्मूलन के लिये प्रयास बढ़ाने के संयुक्त राष्ट्र आम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप 'दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन' पर एक तीन-दिवसीय मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
- इस बैठक में मलेरिया के विरुद्ध एशिया प्रशांत नेताओं का गठबंधन, एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधि, एड्स, टी.बी. एवं मलेरिया के मुकाबले के लिये गठित वैश्विक कोष, मलेरिया उन्मूलन के लिये रणनीतिक सलाहकार समूह के सदस्यों और विभिन्न विकास साझेदारों ने भाग लिया।

इसका निवारण न कर पाने का प्रमुख कारण क्या है?

- अपने पड़ोसी देशों की भाँति भारत में अभी तक मलेरिया को नष्ट न कर पाने का प्रमुख कारण एक कमज़ोर निगरानी प्रणाली है। इसके अलावा, भारत में प्लाज्मोडियम विवैक्स (**Plasmodium Vivax**) के **51%** मामले जो पी.फाल्सीपेरम (**P. Falciparum**) के समरूप ही होता है) पाए गए।
- इसे क्लोरोक्वीन (**Chloroquine**) के प्रतिरोध के रूप में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यह पी.विवैक्स के लिये पहली पंक्ति का उपचार है।

यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का महत्त्व

विधि आयोग द्वारा कहा गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के यातना के विरुद्ध कन्वेंशन (UN Convention Against Torture) की पुष्टि कर देनी चाहिये। गौरतलब है कि दो दशक पहले इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर चुका भारत अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है।

संयुक्त राष्ट्र का यातना के विरुद्ध कन्वेंशन

- यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसकी घोषणा वर्ष **1984** में तथा इसे लागू वर्ष **1987** में किया गया।
- इस कन्वेंशन को वर्तमान में **162** सदस्य अपनी सहमति दे चुके हैं, जबकि **83** पक्ष इसके हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।
- कन्वेंशन को स्वीकृति देने से इनकार करने वाले कुछ देश हैं- अंगोला, बहामा, ब्रुनेई, जाम्बिया, हैती और सूडान आदि। भारत भी इन देशों के साथ इस निंदनीय सूची का हिस्सा है।

कन्वेंशन के उद्देश्य

- इसका उद्देश्य दुनिया भर में होने वाली यातनाओं तथा क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक कृत्यों को रोकना है।
- यह यातना देने को एक दंडनीय अपराध मानता है और पीड़ितों के लिये मुआवज़े के अधिकार को मान्यता देता है।
- यह अपने नागरिक, उन देशों में भेजने से मना करता है, जहाँ यह संभावना है कि उन्हें यातना झेलनी पड़ सकती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

रोहिंग्या मुद्दे पर बांग्लादेश-म्याँमार समझौता

- बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी के लिये म्याँमार के साथ समझौता किया है। इसके तहत बांग्लादेश में शरणार्थी बनकर रह रहे लगभग **6.2** लाख रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्याँमार भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (**UNHCR**), म्याँमार और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए बना एक संयुक्त कार्यशील समूह इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करेगा।
- शरणार्थियों को वापस भेजने का यह समझौता अक्तूबर **2016** के बाद म्याँमार से भागकर बांग्लादेश आए मुसलमानों पर लागू होगा। यह समझौता उन **2** लाख मुसलमानों पर लागू नहीं होगा, जो अक्तूबर **2016** के पहले बांग्लादेश आए हैं।

विदेश व्यापार नीति (2015-20) की मध्यावधि समीक्षा ज़ारी

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार नीति (2015-20) की मध्यावधि समीक्षा जारी की गई है। इसके साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा देश में रोज़गार की संभावनाओं में वृद्धि के लिये नीतिगत उपाय किये जाने की उम्मीद जताई गई है।

प्रमुख बिंदु

- विदेश व्यापार नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों, श्रमोन्मुखी उद्योगों और कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- वस्तु निर्यात योजना (**MEIS**) और सेवा निर्यात योजना (**SEIS**) का दायरा बढ़ाया जाएगा।
- श्रम बहुल उद्योगों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से निर्यात के लिये **MEIS** के अंतर्गत प्रोत्साहन दर **2%** बढ़ाई गई।
- सेवा क्षेत्र में भी निर्यात को बल देने के लिये **SEIS** के अंतर्गत प्रोत्साहन दर **2%** बढ़ाई गई।

निष्कर्ष

विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा का उद्देश्य व्यापार नियमों को आसान कर निर्यात को बढ़ावा देना, उच्च रोज़गार क्षेत्रों को समर्थन देना, जीएसटी सेवाओं का पर्याप्त लाभ उठाना, सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना एवं निर्यात निष्पादन की निगरानी करना है। विदेश व्यापार नीति की समीक्षा में कहा गया है कि भारत अब जीएसटी सुविधाओं के ज़रिये अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिका के बाज़ारों में निर्यात को बढ़ावा देगा।

साइबर हमलों से रक्षा हेतु एन.आई.सी.-सी.ई.आर.टी. केंद्र की उपयोगिता

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत, "एनआईसी-सीईआरटी" केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र के उद्घाटन के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा 'डिजिटल भारत' पहल के तहत अन्य कई सेवाओं को भी ऑनलाइन किया गया।

डिज़िटल लॉकर

- भारत को डिज़िटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिये सरकार एक कार्यक्रम पर कार्य कर रही है। इसके लिये डिज़िटल लॉकर से लेकर विमुद्रीकरण जैसे कई कदम उठाए गए हैं।
- डिज़िटल अर्थव्यवस्था के बनने से आर्थिक विकास में नई लहर आने की संभावना है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि होगी तथा रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।
- यह डिज़िटल इंडिया कार्यक्रम का एक अहम् हिस्सा है। यह दस्तावेज़ों की छायाप्रति सुरक्षित रखने के काम आती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रबंधित इस वेबसाइट आधारित सेवा के ज़रिये उपयोगकर्त्ता अपने दस्तावेज़ों को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं।
- ठीक, इसी प्रकार डिज़िटल अर्थव्यवस्था की अपनी चुनौतियाँ भी हैं। डिज़िटल अर्थव्यवस्था के बनने से बड़ी मात्रा में ग्राहकों एवं नागरिकों के डाटा को डिज़िटल रूप में रखने की आवश्यकता पड़ेगी तथा बड़ी मात्रा में ऑनलाइन विनिमय भी होंगे, जिसके कारण भारत साइबर अपराधियों एवं हैकरों का बड़ा लक्ष्य बन सकता है। इसलिये, इस चुनौती से निपटने के लिये विभिन्न दावेदारों को अपनी तैयारी बेहतर बनानी होगी।

WTO में 'ब्यूनस आयर्स घोषणा-पत्र' का भारत ने किया विरोध

ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) में चल रहे विश्व व्यापार संगठन के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान व्यापार में महिलाओं की भागीदारी पर एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया, जिसे WTO के 119 सदस्य राष्ट्रों का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसे 'महिलाओं और व्यापार पर ब्यूनस आयर्स घोषणा-पत्र' नाम दिया गया। भारत ने इस घोषणा-पत्र का विरोध किया है।

क्या होगा इस घोषणा पत्र का प्रभाव?

- कहा जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में शामिल प्रावधानों के पालन से दुनिया में महिलाओं को बेहतर वेतन वाली नौकरियाँ मिलेंगी।
- इससे संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायता मिलेगी।
- साथ ही, लैंगिक समानता पर आधारित सतत् विकास लक्ष्य की ओर किये जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा।
- व्यापार गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी से **2025** तक वैश्विक **GDP** में **28** ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है।

भारत द्वारा इसका विरोध करने के पीछे तर्क

भारत का कहना है कि यह घोषणा-पत्र एक लैंगिक मुद्दे को WTO से जोड़ता है, जबकि लैंगिक मुद्दे का व्यापार से कोई लेना-देना नहीं है।

- यदि आज **WTO** में किसी लैंगिक मुद्दे को जगह दी जाती है, तो भविष्य में श्रम और पर्यावरणीय मानकों जैसे मुद्दे भी इस मंच पर जगह पाना चाहेंगे। एक कोर व्यापारिक संगठन होने के नाते **WTO** को स्वयं को सिर्फ व्यापारिक मुद्दों तक सीमित रखना चाहिये।
- उन्नत देश महिला-व्यापार संबंधी नीतियों में उच्च मानकों का उपयोग कर विकासशील देशों के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं और इससे विकासशील देशों में महिलाओं को मिलने वाले इंसेंटिव या प्रोत्साहन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- **WTO** की मुक्त व्यापार नीतियों का नुकसान सीमांत किसानों खासकर महिला किसानों को उठाना पड़ा है।

क्या है येरुशलम शहर का महत्त्व एवं विवाद का कारण?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल एवं फिलिस्तीन के मध्य बहुत लम्बे समय से चले आ रहे विवाद को दरकिनार करते हुए एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने द्विराष्ट्र की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए येरुशलम (अल कुद्स) को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान की।

मुख्य बिंदु

- इज़राइलियों और फ़लस्तीनियों के पवित्र शहर येरुशलम को लेकर विवाद बहुत पुराना और गहरा है। यह शहर न केवल इस्लाम और यहूदियों के लिये महत्त्वपूर्ण है बल्कि यह ईसाई धर्म और अर्मेनियाई लोगों के लिये भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र स्थान है।
- इसका सबसे अहम् कारण यह है कि ये तीनों संप्रदाय पैगंबर इब्राहीम को अपने-अपने धार्मिक इतिहास का अहम् अंग मानते हैं। यह दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, (+91)8130392354, 56
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस शहर के केंद्र में एक प्राचीन शहर बसता है, जिसे ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके चारों ओर एक किलेनुमा सुरक्षा दीवार अवस्थित है।
- मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने एक रात में मक्का से यहाँ तक की यात्रा की थी।
- इसके नजदीक 'डोम ऑफ द रॉक्स' का पवित्र स्थल स्थित है। इसे पवित्र पत्थर भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार, यह वही स्थान है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा की थी।

विवाद का कारण क्या है?

- फलस्तीनी और इज़राइलियों के मध्य विवाद का मुख्य कारण प्राचीन येरुशलम शहर है। यह क्षेत्र केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक एवं कूटनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम् है।
- इस क्षेत्र की भौगोलिक अथवा राजनीतिक स्थिति में ज़रा सा भी परिवर्तन हिंसक तनाव का रूप धारण कर लेता है।
- यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान बेहद चौंकाने वाला है, विशेषकर तब जब समस्त विश्व के नेताओं द्वारा इस संबंध में अपील की गई।

भारत बना 'वासेनर अरेंजमेंट' का 42वाँ सदस्य

भारत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उत्कृष्ट निर्यात नियंत्रण पर निगरानी रखने वाली संस्था वासेनर अरेंजमेंट (WA-Wassenaar Arrangement) का 42वाँ सदस्य बन गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी सफलता माना जा रहा है।

क्या है वासेनर अरेंजमेंट?

इसकी स्थापना 1996 में वासेनर (नीदरलैंड) में की गई थी। यह परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) की तरह ही परमाणु अप्रसार की देख-रेख करने वाली संस्था है। वासेनर अरेंजमेंट सदस्य देशों के बीच परंपरागत हथियारों, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय वियना में है।

WTO के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा पर वार्ता विफल

अमेरिका के सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान तलाशने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने के कारण ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) में चल रही WTO की 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक बिना किसी महत्त्वपूर्ण घोषणा के समाप्त हो गई।

क्या है मुद्दा?

- विश्व व्यापार संगठन का कोई भी सदस्य देश हर साल अपनी पैदावार की कीमत का **10%** से ज़्यादा खाद्य सब्सिडी नहीं दे सकता है। पैदावार की कीमत के आकलन के लिये **1986-88** को आधार बनाया गया है।
- भारत ने इस पर आपत्ति ज़ाहिर करते हुए कहा कि देश में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने पर सब्सिडी **10%** से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिये भारत को इस नियम में विशेष छूट दी जानी चाहिये।
- इसके समाधान के लिये **WTO** की **2013** में बाली में हुई बैठक में "पीस क्लॉज़' नाम से एक अस्थायी समाधान निकाला गया।
- इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के साथ भारत का गतिरोध जारी रहा और अमेरिका ने इसके स्थायी समाधान के लिये किये जाने वाले किसी भी प्रयास में शामिल होने से इनकार कर दिया।

जब तक इस मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक भारत 'पीस क्लॉज़' के अंतर्गत मिली छूट का लाभ उठाता रहेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विश्व व्यापार संगठन की 11वीं मंत्रिस्तरीय वार्ता में गतिरोध

विकसित तथा विकासशील देशों के हितों के टकराव के कारण ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की 11वीं मंत्रिस्तरीय वार्ता बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई। खाद्य सुरक्षा तथा विकास से संबंधित अन्य मुद्दों पर 'पीस क्लॉज़' (Peace clause) के तहत, यथास्थिति बने रहने के कारण भारत समेत अन्य विकासशील देशों के हित फिलहाल सुरक्षित हैं किन्तु इन मुद्दों पर कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
मुद्दा क्या है?

- विश्व व्यापार संगठन के दोहा राउंड के तहत विकास को महत्त्व प्रदान करते हुए विकासशील देशों को छूट प्रदान की गई थी। विकसित देश विकास के मुद्दे से बाहर निकल कर आर्थिक हितों पर बल देना चाहते हैं।
- इसी मुद्दे पर अमेरिका ने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि विकास को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है, ताकि कुछ सक्षम देश विकास के नाम पर अपने हितों को साध नहीं पाएँ। यहाँ उनका इशारा भारत तथा चीन जैसे देशों की तरफ था, जो जी.डी.पी. के आधार पर विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभर रहे हैं।
- अमेरिका का यह आरोप बेबुनियाद है क्योंकि वर्तमान समय में एक देश के रूप में सर्वाधिक निर्धन तथा कुपोषित लोग भारत में ही निवास करते हैं।
- अमेरिका द्वारा भारत के खाद्य सुरक्षा अधिनियम, **2013** का विरोध इस आधार पर किया गया कि इससे खाद्य वस्तुओं की कीमत कम होने के कारण, इनके स्वतंत्र व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किन्तु, भारत का तर्क यह है कि देश की कुपोषण और भुखमरी से संबंधित समस्या के समाधान के लिये यह अधिनियम अत्यंत आवश्यक है।

परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में भारत को रूस का समर्थन

हाल ही में रूस द्वारा भारत को परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers' Group) में शामिल करने हेतु समर्थन जारी रखने की बात कही गई है। रूस द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि 15वीं आर.आई.सी. (Russia, India, China - RIC) विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के साथ इस मुद्दे के संबंध में पुन: बातचीत की जाएगी।

एन.एस.जी. क्या है?

- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (एनएसजी) **48** देशों का समूह है। इसका लक्ष्य परमाणु सामग्री, तकनीक एवं उपकरणों के निर्यात को नियंत्रित करना है। परमाणु हथियार बनाने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक सभी, इसी के दायरे में आते हैं।
- इसका गठन **1974** में भारत के परमाणु परीक्षण के प्रतिक्रियास्वरूप किया गया था। वर्तमान में इसके **48** सदस्य राष्ट्र हैं।

एनपीटी क्या है?

- एनपीटी अर्थात् परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है।
- एनपीटी की घोषणा **1970** में हुई थी और अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के **188** सदस्य देशों ने इसके पक्ष में समर्थन दिया है।
- इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते।
- भारत, पाकिस्तान, इज़राइल, उत्तरी कोरिया और दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र के ऐसे सदस्य देश हैं, जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय घटनाक्रम

एशियन हार्मोनाइज़ेशन वर्किंग पार्टी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एशियन हार्मोनाइजेशन वर्किंग पार्टी (AHWP) के 22वें सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एशिया और उसके बाहर के क्षेत्रों में चिकित्सीय उपकरणों के नियमन का अभिसरण करना।
- एकरूपता हेतु दृष्टिकोण विकसित करने के लिये सुझाव देना।
- नियामकों एवं इस उद्योग के बीच ज्ञान तथा विशेषज्ञता के आदान-प्रदान मकी सुविधा प्रदान करना।

राष्ट्रीय ट्रेकोमा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014 -17

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ट्रेकोमा सर्वेक्षण रिपोर्ट (National Trachoma Survey Report, 2014-17) जारी की गई। भारत अब 'रोग पैदा करने वाले ट्रेकोमा' से मुक्त हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- सर्वेक्षण के निष्कर्षों से प्राप्त जानकारी से स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिन ज़िलों में सर्वेक्षण कार्य को संपन्न किया गया, वहाँ बच्चों में ट्रेकोमा का संक्रमण लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है।
- वस्तुतः ट्रेकोमा को उस स्थिति में समाप्त माना जाता है, जब **10** वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उसके सक्रिय संक्रमण की मौजूदगी **5** प्रतिशत से भी कम हो।

सरकार का लक्ष्य क्या है?

- सरकार का लक्ष्य देश से ट्रेकोमेट्सस्ट्रीचियासिस (**Trachomatoustrichiasis**) को पूरी तरह से समाप्त करना है।

ट्रेकोमा (Trachoma) क्या है?

- ट्रेकोमा [रोहे-कुक्करे (**Rohe/Kukre)]** आँखों का एक दीर्घकालिक संक्रमण रोग है। यह अंधेपन का सबसे अहम कारण है।
- यह खराब पर्यावरण और निजी स्तर पर स्वच्छता के अभाव तथा पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण होने वाली बीमारी है।
- यह आँखों की पलकों के नीचे की झिल्ली को प्रभावित करता है। बार-बार संक्रमण होने पर आंखों की पलकों पर घाव होने लगते हैं। इससे कोर्निया को नुकसान पहुँचता है और अंधापन होने का खतरा पैदा हो जाता है।

अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला समुदाय दिवस

नीति आयोग द्वारा 15 दिसंबर को अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के समुदायिक दिवस (Atal Tinkering Lab's Community Day) के रूप में मनाया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उद्देश्य

- अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला समुदायिक अभियान पहल का उद्देश्य समुदाय के ऐसे बच्चों तक नवाचार फैलाकर अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के प्रभाव को बढ़ाना है, जो औपचारिक शिक्षण संस्थानों से संबद्ध नहीं हैं।
- इस पहल का ध्येय इन बच्चों को समस्या का समाधान करने योग्य बनाने के लिये अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के छात्रों के समान ही शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराना है।

अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला

- नीति आयोग ने अपने प्रमुख कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन (**Atal innovation Mission)** के हिस्से के रूप में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला (**Atal Tinkering Lab)** नामक पहल की शुरुआत की है।
- माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिये नीति आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के स्कूलों में प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की योजना बनाई है।

प्रमुख विशेषताएँ तथा उद्देश्य

- अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसा कौशल प्रदान करना और उन्हें उस प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करना है जो उन्हें समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगी।
- नीति आयोग के अनुसार यदि भारत को अगले तीन दशकों में निरंतर **9** से **10** प्रतिशत विकास दर कायम रखनी है तो यह अत्यंत आवश्यक होगा कि देश समस्याओं के लिये अभिनव समाधान के उपाय करने में सक्षम हो।

मेघालय ने 'सामाजिक अंकेक्षण' को दिया आधिकारिक दर्जा

मेघालय सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण को सरकारी काम-काज का हिस्सा बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने हाल ही में 'मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम **2017**' लागू किया है।
- यह देश में पहली बार है कि किसी राज्य ने सामाजिक अंकेक्षण को सरकारी तंत्र में आधिकारिक तौर पर शामिल किया है।

वड़ोदरा में भारत का पहला राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वड़ोदरा में देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय (National Rail and Transport University – NRTU) स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की।

- इस विश्वविद्यालय को यू.सी.जी. की नोवो श्रेणी (**novo category)** नियमन (**Institutions Deemed to be Universities, Regulations), 2016** के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- इस विश्वविद्यालय/संस्थान का वित्त-पोषण पूरी तरह से रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

लाभ

- यह विश्वविद्यालय न केवल भारतीय रेल को आधुनिकीकरण के रास्ते पर ले जाएगा, बल्कि रेलवे की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। वस्तुतः यह परिवहन क्षेत्र में भारत को विश्व स्तरीय पहचान बनाने में सहायता प्रदान करेगा।
- भारत वैश्विक साझेदारी और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से विशेषज्ञता के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा।

गंगा ग्राम परियोजना

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर को नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी के तट पर स्थित गाँवों में संपूर्ण स्वच्छता का अनुपालन करना है।

प्रमुख बिंदु

- अगस्त, **2017** में **5** गंगा राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल) के सक्रिय सहयोग से मंत्रालय द्वारा सभी **4470** गंगा गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।
- गंगा तट पर बसे गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के पश्चात् मंत्रालय व राज्य सरकारों द्वारा **24** ऐसे गाँवों की पहचान की गई, जिन्हें गंगा ग्राम के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इन गाँवों के माध्यम से स्वच्छता का मानदंड स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।
- इन गाँवों को **31** दिसंबर, **2018** तक गंगा ग्राम में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नोडल निकाय

- स्वच्छ भारत मिशन के लिये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

लक्ष्य

- गंगा ग्राम परियोजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से गंगा तट पर बसे गाँवों के संपूर्ण विकास के लिये एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना है।
- गंगा ग्राम परियोजना के अंतर्गत ठोस और द्रव कचरा प्रबंधन, तालाबों और अन्य जलाशयों के पुनरुद्धार, जल संरक्षण परियोजनाओं, जैविक खेती, बागवानी तथा औषधीय पौधों को प्रोत्साहन देने जैसे घटकों को शामिल किया गया है।

सलाहकार समिति का गठन

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जो इस संबंध में आवश्यक सभी प्रकार की नीतियों के निर्माण के साथ-साथ सभी ज़रूरी निर्णय लेगी।
- इसके अतिरिक्त एक अन्य समिति का भी गठन किया गया है, जो परियोजना का पर्यवेक्षण करेगी, समन्वय स्थापित करेगी तथा इसे लागू करेगी।

गंगा स्वच्छता मंच का गठन

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री की पहल पर एक गंगा स्वच्छता मंच का गठन किया गया है। इस मंच में शिक्षाविदों और नागरिक संगठनों के साथ-साथ आम नागरिकों की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया गया है।

सरकार द्वारा 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा अर्जित करने हेतु किये गए प्रयास

भारत सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम आरंभ किया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन

- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (**National Solar Mission**) का उद्देश्य फॉसिल आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के अंतिम उद्देश्य सहित बिजली सृजन एवं अन्य उपयोगों के लिये सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है।
- वर्ष **2022** तक **175** गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने के लिये पिछले दो वर्षों के दौरान सोलर पार्क, सोलर रूफटॉप योजना, सौर रक्षा योजना, नहर के बांधों तथा नहरों के ऊपर सीपीयू सोलर पीवी पॉवर प्लांट हेतु सौर योजना, सोलर पंप, सोलर रूफटॉप आदि के क्रियान्वयन के लिये कई बड़े कार्यक्रम/योजनाएँ आरंभ की गई हैं।

वित्तीय समर्थन हेतु किये गए नीतिगत उपाय

- वर्ष **2022** तक **175** गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने के लिये नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं को वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त विभिन्न नीतिगत उपाय आरंभ करने के साथ-साथ विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।
- इनमें नवीकरणीय खरीद बाध्यता (**Renewable Purchase Obligation - RPO**) के मज़बूत क्रियान्वयन और नवीकरणीय सृजन बाध्यता (**Renewable Generation Obligation - RGO**) हेतु बिजली अधिनियम एवं टैरिफ नीति में अनुकूल संशोधन करना शामिल है।
- साथ ही हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के माध्यम से बिजली पारेषण नेटवर्क का विकास करना।

इंसेफलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) के नए कारक की खोज

भारतीय पत्रिका 'करेंट साइंस' में ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले में पाई जाने वाली मस्तिष्क सूजन बीमारी को इंसेफलाइटिस के लिये एक नया और अप्रत्याशित कारण बताया गया है।

प्रमुख बिंदु

- कई सालों से इंसेफलाइटिस की आवर्ती महामारी का कारण जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) वायरस को माना जाता रहा है।
- अब शोधकर्त्ताओं का कहना है कि इस बीमारी का कारण इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से उगने वाली 'बडा चकुंडा' (**Bada Chakunda**) नामक जंगली सेम (**Wild Bean**) का उपभोग है।

इंसेफलाइटिस क्या है?

- इंसेफलाइटिस को प्राय: जापानी बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि यह जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) नामक वायरस के कारण होता है।
- यह एक प्राणघातक संक्रामक बीमारी है, जो फ्लैविवायरस के संक्रमण से होती है। यह मुख्य रूप से उन बच्चों को प्रभावित करती है, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली वयस्कों की तुलना में काफी कमज़ोर होती है।
- क्यूलेक्स मच्छर इस बीमारी का वाहक होता है। सूअर तथा जंगली पक्षी मस्तिष्क ज्वर के विषाणु के स्रोत होते हैं।

नए कारक की खोज के कारण

इसके तहत इंसेफेलाइटिस के मामले की जेई के रूप में पुष्टि नहीं होने पर चिकित्सक इसे **एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (Acute Encephalitis Syndrome-AES)** नाम देते है जो कि अलग-अलग अनामित (Unnamed) रोगों के लिये प्रयुक्त एक अप्रचलित और अस्थायी संकेत है। इससे बीमारी के वास्तविक कारण का पता लगाने के प्रयास हतोत्साहित होते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से पूर्वोत्तर में व्यवसाय और रोज़गार की नई राह

केंद्रीय शिपिंग, सड़क परिवहन राजमार्ग जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा असम में शिपिंग मंत्रालय के फ्लैगशिप सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग – 2 (National Waterway - NW 2 के माध्यम से पहले सीमेंट कार्गो परिवहन का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह कदम देश में आर्थिक रूप से मज़बूत और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों को बढ़ावा देने के भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के रूप में मील का पत्थर साबित होगा।
- इस मार्ग के माध्यम से **200-200** मीट्रिक टन क्षमता वाले दो माल ढुलाई पोत कुल **400** मीट्रिक टन सीमेंट भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (**Inland Waterways Authority of India's)** के पाण्डु बंदरगाह (**Pandu Port)** से **255** किलोमीटर की दूरी तय कर ढुबरी (**Dhubri)** ले जाने में सक्षम होंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आर्थिक घटनाक्रम

वेनेज़ुएला की नई क्रिप्टोकरेंसी: 'पेट्रो'

वेनेज़ुएला ने 'पेट्रो' नामक अपनी एक नई आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) जारी करने की घोषणा की है। इस नई मुद्रा का उपयोग वेनेज़ुएला के तेल, गैस, सोना और हीरा उद्योग कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- पेट्रो एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है।
- क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, इंटरनेट करेंसी, ई-करेंसी या पीपुल्स-करेंसी भी कहा जाता है।
- इस मुद्रा के उपयोग और भुगतान के लिये क्रिप्टोग्राफी नामक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
- विश्व की पहली क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन है।
- क्रिप्टोकरेंसी को कहीं भी आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है तथा किसी अन्य मुद्रा जैसे- डॉलर, यूरो आदि में भी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है।
- क्रिप्टोकरेंसी से कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। यह बेहद उछाल और गिरावट वाली मुद्रा है। बिटकॉइन की चोरी या घोटाले जैसी ख़बरों से ही इसकी कीमतों में गिरावट आ जाती है।
- इसे खरीदने और बेचने वालों का एक-दूसरे से अपरिचित होना भी एक प्रकार का जोखिम है।
- क्रिप्टोकरेंसी का कोई नियामक प्राधिकरण नहीं है। धोखाधड़ी होने की स्थिति में ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है, जिसके समक्ष इसकी शिकायत लेकर जाया जा सके।

एफ.आर.डी.आई. विधेयक के उद्देश्य एवं महत्त्व

11 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक, 2017 (Financial Resolution and Deposit Insurance Bill) अभी संसद की संयुक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है।

मुख्य बिंदु

- एफ.आर.डी.आई. विधेयक में निहित प्रावधानों से जमाकर्त्ताओं को वर्तमान में मिल रहे संरक्षण में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इनसे जमाकर्त्ताओं को कहीं ज़्यादा पारदर्शी ढंग से अतिरिक्त संरक्षण प्रदान किया गया है।
- एफ.आर.डी.आई. विधेयक दूसरे न्याय-अधिकारों अथवा क्षेत्राधिकारों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अनुकूल है। इसके अंतर्गत संकट से उबारने हेतु बहुत से वैधानिक प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिसके लिये लेनदारों/जमाकर्त्ताओं की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- एफ.आर.डी.आई. विधेयक एक व्यापक समाधान व्यवस्था सुनिश्चित करके बैंकिंग प्रणाली को और मज़बूत करेगा।

एफ.आर.डी.आई. विधेयक, 2017

- इस विधेयक के अंतर्गत बैंकों और बीमा जैसे व्यवसायों में दिवालियापन को शामिल किया गया है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, (+91)8130392354, 56
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस विधेयक में वित्तीय रिज़ॉल्यूशन के अंतर्गत पूंजी और परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर व्यवहार्यता आधारित 'भौतिक' अथवा 'आसन्न' जोखिम जैसी स्थितियों का सामना कर रहे बैंकों के लिये समाधान को भी शामिल किया गया है।
- इस विधेयक में 'बेल-इन' के प्रावधान का भी परिचय दिया गया है, जिसका उद्देश्य बैंक के नुकसान को अवशोषित करने और इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये पूंजी प्रदान करना है।
- यहाँ यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि यहाँ अस्तित्व का मतलब जमाकर्त्ताओं के पैसे की सुरक्षा नहीं है, बल्कि बैंक की पूंजी को बहाल करना है।

सरकार चुकाएगी ई-पेमेंट पर ट्रांज़ेक्शन लागत

केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्णय लिया है कि 1 जनवरी, 2018 से दो सालों तक 2 हज़ार तक के डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का वहन वह स्वयं करेगी।

क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट?

- मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क होता है, जो बैंक किसी भी दुकानदार या कारोबारी से कार्ड पेमेंट सेवा के लिये लेता है। कार्ड ट्रांज़ेक्शन के लिये प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (**POS**-मशीन) बैंक की ओर से लगाई जाती है।
- बैंक द्वारा एमडीआर के तौर पर कमाई गई राशि में से कार्ड जारी करने वाले बैंक और कुछ हिस्सा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे- वीजा, मास्टरकार्ड को दिया जाता है। इस शुल्क के कारण ही दुकानदार कार्ड से पेमेंट के प्रति अरुचि प्रकट करते हैं। कई कारोबारी एमडीआर शुल्क का भार ग्राहकों पर डालते हैं।
- यह दर आरबीआई ही तय करती है।

प्रमुख बिंदु

- डेबिट कार्ड, भीम एप तथा यूपीआई के ज़रिये **2000** रुपए तक लेन-देन करने पर एमडीआर शुल्क का वहन सरकार स्वयं करेगी।
- इस छूट का मुख्य उद्देश्य कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देना है।

वी.ओ.एल.टी.ई. सेवाएँ

दूरसंचार सेवा प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) द्वारा अपनी दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के तहत चेन्नई में ग्राहकों के लिये एक वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (Voice over Long Term Evolution - VoLTE) सुविधा शुरू की गई है।

मुख्य बिंदु

- भारतीय दूरसंचार कंपनी बाज़ार में अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति को बनाए रखने के लिये पुरज़ोर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में वी.ओ.एल.टी.ई. (वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन) सेवाएँ आरंभ की गई हैं।

वी.ओ.एल.टी.ई. क्या है?

- वी.ओ.एल.टी.ई. का अर्थ है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (**voice over Long Term Evolution)**।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- वी.ओ.एल.टी.ई. विभिन्न सेवाओं को मूल रूप से आवाज़ या वीडियो के लिये अलग-अलग एप्लीकेशन पर स्विच करने की बजाय नेटवर्क पर संचालित करने में सक्षम बनाता है।

यह किस प्रकार कार्य करता है?

- वी.ओ.एल.टी.ई. मोबाइल फोन नेटवर्क द्वारा उपयोग किये जाने वाले एल.टी.ई. प्रोटोकॉल (**Long Term Evolution protocol)** के लिये एक प्रौद्योगिकी अपडेट (**technology update)** है।
- एल.टी.ई. के तहत दूरसंचार कंपनियों का बुनियादी ढाँचा केवल आँकड़ों के प्रसारण की अनुमति देता है, जबकि वॉइस कॉल उनके पुराने **2**जी या **3**जी नेटवर्क के माध्यम से ही संपन्न होती हैं।
- यही कारण है कि एलटीई सेवाओं के तहत **4**जी डेटा सेवाओं तक पहुँच बनाना कठिन हो जाता है।
- यह धीमी इंटरनेट गति और खराब आवाज़ स्पष्टता जैसी समस्याओं को बढ़ावा देता है।
- वी.ओ.एल.टी.ई. पारंपरिक आवाज़ की तुलना में न केवल स्पेक्ट्रम का और अधिक कुशल तरीके से उपयोग सुनिश्चित करता है, बल्कि इससे मोबाइल फोन की बैटरी भी लंबे समय तक चलती है।

4जी तकनीक क्या है?

- **4**जी एक वायरलेस मोबाइल तकनीकी है। यह एक ऐसी मोबाइल नेटवर्क सेवा है जिसके अंतर्गत इंटरनेट का प्रयोग करते हुए **3**जी सेवाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र गति के साथ डेटा अपलोड तथा डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

स्पीड

- **3**जी स्पीड - औसतन **5** (अपलोड) से **14** (डाउनलोड) एम.बी.पी.एस.
- **4**जी स्पीड - **50** (अपलोड) से **100** (डाउनलोड) एम.बी.पी.एस.

4जी एल.टी.ई. क्या है?

- यह एक नई वायरलेस मोबाइल ब्रॉड्बैंड तकनीक है, जो **4**जी नेटवर्क पर कार्य करती है। इसके माध्यम से बहुत तीव्र गति से डेटा ट्रांसमिशन किया जा सकता है।

4जी और 4जी एल.टी.ई. तकनीक में क्या अंतर है?

- जब **4**जी तकनीक को शुरू किया गया था तो स्पष्ट किया गया था कि यह तकनीक **3**जी तकनीक से अधिक तीव्र होगी। यही कारण था कि इस तकनीक के आने के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अपने बैंडविड्थ पर **4**जी सेवाएँ प्रदान करनी शुरू कर दी गई।
- हालाँकि, कंपनियाँ उपभोक्ताओं को उतनी अधिक तीव्र गति की सेवा प्रदान करने में सफल नहीं हो पाई जितना कि उन्होंने दावा किया था।
- इस समस्या को ध्यान में रखते हुए **4**जी एल.टी.ई. की अवधारणा को पेश किया गया। इस तकनीक के अंतर्गत **3**जी से अधिक तीव्र गति प्रदान की जाएगी, हालाँकि वह गति **4**जी जितनी तीव्र नहीं होगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विकेंद्रीकृत खरीद योजना में सुधार

हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा नीति आयोग से अनाज की खरीद में प्रयोग की जाने वाली प्रवृत्तियों का अध्ययन करने, उस पर विकेंद्रीकृत खरीद योजना (Decentralized Procurement Scheme - DCP) प्रणाली के प्रभाव का आकलन करने और इस योजना के तहत खरीद एजेंसियों की दक्षता तथा प्रभावशीलता का आकलन करने का अनुरोध किया गया है।

एक उच्च स्तरीय समिति

- इस संबंध में श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की स्थापना की गई थी, ताकि अनाज, विपणन, भंडारण, संरक्षण और वितरण की खरीद संबंधी मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जा सके।

विकेंद्रीकृत खरीद योजना (Decentralized Procurement Scheme) क्या है?

- खाद्यान्नों की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देकर अधिकतम सीमा तक स्थानीय खरीद को प्रोत्साहित करने और ढुलाई की लागत में बचत करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष **1997-98** में खाद्यान्नों की 'विकेंद्रीकृत खरीद योजना' की शुरुआत की थी।
- इस योजना के तहत उन खाद्यान्नों की खरीद की जाती है, जो स्थानीय तौर पर अधिक पसंद किये जाते हैं।

ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन हेतु "दर्पण परियोजना"

संचार मंत्रालय द्वारा सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने, सेवाओं में मूल्यवर्द्धन तथा बैंक सेवाओं से वंचित ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिये 'दर्पण – डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया" (DARPAN – "Digital Advancement of Rural Post Office for A New India) परियोजना का शुभारंभ किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- **1400** करोड़ रुपए की इस परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक पोस्ट ऑफिस की शाखा के पोस्ट मास्टर (**Branch Postmaster - BPM)** को कम शक्ति वाली तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
- इसके अंतर्गत सभी राज्यों के ग्रामीण उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार के लिये लगभग **1.29** लाख डाकघरों को शामिल किया जाएगा।
- इस परियोजना में लक्षित उद्देश्य को मार्च**, 2018** तक पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

इससे क्या लाभ होगा ?

- इस परियोजना से ग्रामीण आबादी तक डाक विभाग की पहुँच में विस्तार होगा।
- खुदरा डाक व्यवसाय से राजस्व में वृद्धि होगी।

विद्युत वाहनों हेतु बैटरी से संबंधित अनुसंधान एवं विकास

भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा हाइब्रिड वाहनों सहित सभी विद्युत वाहनों के लिये एक मिशन प्लान अर्थात् एन.ई.एम.एम.पी. (National Electric Mobility Mission Plan 2020 - NEMMP), 2020 तैयार किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- एन.ई.एम.एम.पी. के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से विद्युत एवं हाइब्रिड वाहनों के निर्माण तथा उपयोग में सुविधा हेतु एक रोडमैप तैयार करने का उल्लेख किया गया है, ताकि बैटरी प्रौद्योगिकी सहित अन्य तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास के लिये सहायता दी जा सके।
- इन वाहनों की मांग में वृद्धि करने की दिशा में आवश्यक प्रयास किये जाएंगे ताकि वर्ष **2020** तक इन वाहनों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके।

फेम इंडिया स्कीम

- इस मिशन के तहत भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा **1** अप्रैल, **2015** से क्रियान्वयन के लिये फेम इंडिया स्कीम [**Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid) Electric Vehicles in India**] को अधिसूचित किया गया है।
- यह योजना वर्ष **2020** तक **6** वर्षों की अवधि के लिये क्रियान्वित की गई है। इसके तहत हाइब्रिड/विद्युत वाहन (**hybrid/electric vehicles)** बाज़ार के साथ-साथ इनके विनिर्माण में भी सहायता प्रदान की जाएगी

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और एनपीए समस्या

हाल ही में आरबीआई द्वारा मार्च से सितंबर की अवधि की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial stability report) जारी की गई है।

क्या है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट?

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) एक अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- रिपोर्ट में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेकर ही सवाल नहीं खड़े किये गए हैं बल्कि निजी बैंक भी फँसे हुए कर्ज़ के मामले में बड़ी परेशानी झेल रहे हैं।
- बैंकिंग स्थिरता सूचकांक के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता की हालत बिगड़ रही है।

क्या है बैंकिंग स्थिरता सूचकांक?

- बैंकिंग स्थिरता सूचकांक, बैंकों के लिये परिसंपत्ति गुणवत्ता का एक सूचक है।
- यह इंडेक्स उन परिस्थितियों में आगे संकटग्रस्त होने वाले बैंकों की संख्या प्रदर्शित करता है जब कोई एक बैंक संकटग्रस्त हो चुका होता है।
- यह सूचकांक जितना ही बढ़ता जाता है, बैंकों के संकटग्रस्त होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है।

बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में बेहतरी हेतु किये जा रहे प्रयास

बैंकरप्सी कोड:

- विगत वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापनसंहिता संबंधी विधेयक पारित किया था।
- यह नया कानून **1909** के 'प्रेसीडेंसी टाऊन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट **1920**' को रद्द करता है तथा कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इंद्रधनुष योजना:

- देश के सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिये सरकार ने वर्ष **2015** में एक सात सूत्री इंद्रधनुष योजना बनाई थी।
- इंद्रधनुष' योजना का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, एनपीए में कमी करना और बैंकों का प्रदर्शन सुधारना है।
- 'इंद्रधनुष' के अंतर्गत पुनर्पूंजीकरण के उपाय किये जा रहे हैं और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कम करने में मदद की जा रही है।

पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर)

- हाल ही में पीसीआर बनाने को लेकर आरबीआई ने एक कार्यदल का गठन किया था। दरअसल, पीसीआर क्रेडिट से संबंधित जानकारियों का एक विस्तृत डाटाबेस होगा जो सभी हितधारकों के लिये उपलब्ध रहेगा।
- पीसीआर में ऋण की मांग करने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारियाँ, जैसे- उसने पहले कितना ऋण लिया है, उसने समयानुसार ऋण चुका दिया है या नहीं, आदि एकत्र कर रखी जाएंगी.
- आमतौर पर पीसीआर का प्रबंधन केंद्रीय बैंक या बैंकिंग पर्यवेक्षक के हाथ में होता है और कानूनी तौर पर कर्ज़दाताओं या कर्ज़दारों के लिये ऋण विवरणों की सूचना पीसीआर को देना अनिवार्य बना दिया जाता है।

अमेरिकी सुरक्षा मानकों पर आधारित होगी भारत की पहली पॉड टैक्सी

परिवहन विशेषज्ञ एस.के. धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय समिति ने भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा प्रारंभ करने के लिये तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों पर आधारित नवीन दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु :

- पॉड टैक्सी योजना **4000** करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (**NHAI**) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

पॉड टैक्सी सेवा क्या है?

- पॉड टैक्सी सेवा एक आधुनिक और उन्नत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। इसे पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (**PRT**) भी कहा जाता है।
- इसमें सामान्य टैक्सी सेवाओं की तरह ही यात्रियों के छोटे समूहों को मांग आधारित फीडर एवं शटल सेवाएँ प्रदान कराई जाती हैं, किंतु इसमें स्वचालित इलेक्ट्रिक पॉड का इस्तेमाल किया जाता है। यह परिवहन का एक स्वच्छ एवं हरित विकल्प है।
- यह सेवा ट्रैफिक जाम और प्रदूषकों के उत्सर्जन जैसी समस्याओं से मुक्त है तथा आवागमन के लिये एक किफायती माध्यम है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ऑटोमेटेड पीपुल मूवर (Automated People Mover-APM) मानक निर्धारित किये जाते हैं, जिनमें सुरक्षा और निष्पादन के न्यूनतम स्तर तय किये जाते हैं। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा भी इन्हीं मानकों पर आधारित होगी।

मेथनॉल इकॉनमी फण्ड

नीति आयोग द्वारा स्वच्छ ईंधन के उत्पादन और प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु 4000-5000 करोड़ की राशि वाले मेथनॉल इकॉनमी फण्ड को स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उद्देश्य :

- **1** जनवरी, **2018** से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में मेथनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देना।

मेथनॉल (CH3OH) :

- मेथनॉल को काष्ठ एल्कोहल (**Wood Alcohal**) भी कहा जाता है। यह एक बायोडिग्रेडेबल अर्थात् जैव-अपघटनीय पदार्थ है।
- यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रंगहीन और स्वच्छ तरल पदार्थ है, जिसे प्राकृतिक गैस, कोयला और नवीकरणीय फीडस्टॉक्स की विस्तृत श्रृंखला से भी उत्पादित किया जा सकता है।
- मेथनॉल एक स्वच्छ, सस्ता, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा विकल्प के रूप में उभरा है जिसका उपयोग परिवहन ईंधन और खाना पकाने के ईंधन के लिये किया जा सकता है।
- अगले कुछ वर्षों में यह भारत के तेल आयात बिल में अनुमानित **20** प्रतिशत तक कटौती करने में सहायक हो सकता है।
- यह एक उच्च कुशल ईंधन है, जिसे गैसोलीन / डीज़ल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। यह नाइट्रोजन और सल्फाइड के ऑक्साइड्स (**NOx & SOx**) तथा पर्टिकुलेट मैटर (**PM**) की कम मात्रा का उत्सर्जन करता है।

भारत की मेथनॉल अर्थव्यवस्था : विकास का नया रूप

मेथनॉल बनाने की नई प्रणाली का इस्तेमाल रसायनों और प्लास्टिक बनाने के लिये भी किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- यह न केवल लागत में बहुत सस्ता है, बल्कि इसका पेट्रोल की अपेक्षा पर्यावरण के अनुकूल होने का भी वादा किया जा रहा है।
- वर्तमान में मीथेन को सर्वप्रथम तरल प्राकृतिक गैस (**Liquid Natural Gas**) के रुप में संघनित किया जाता है, तत्पश्चात् इसे दबाव वाले कंटेनरों (**Pressurised Containers**) में भरा जाता है।
- वर्तमान में भारत को प्रतिवर्ष तकरीबन **2900** करोड़ लीटर पेट्रोल और **9000** करोड़ लीटर डीज़ल की आवश्यकता है।
- ईंधन खपत के संदर्भ में भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।
- हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मेथनॉल (**Methanol**) के निर्माण का एक नया तरीका खोजा गया है। मेथनॉल का इस्तेमाल वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा हवा में ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए एक ऐसी तकनीक का निर्माण किया गया है, जिसका प्रयोग हरित औद्योगिक प्रक्रियाओं (**Greener Industrial Processes**) के संबंध में किया जा सकता है।

मेथनॉल की विशेषताएँ

- मेथनॉल एक हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील द्रव होता है।
- यह सबसे सरल अल्कोहल होता है।
- यह जैव ईंधन के उत्पादन में बेहद उपयोगी होता है।
- यह एक कार्बनिक यौगिक है, इसे काष्ठ अल्कोहल भी कहते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

मेथनॉल ही क्यों?

- मेथनॉल ईंधन में विशुद्ध ज्वलन कण विद्यमान होते हैं जो परिवहन में पेट्रोल और डीज़ल दोनों और रसोई ईंधन में एलपीजी, लकड़ी एवं मिट्टी तेल का स्थान ले सकता है।
- यह रेलवे, समुद्री क्षेत्र, जेनसेट्स, पावर जेनरेशन में डीज़ल को भी प्रतिस्थापित कर सकता है और मेथनॉल आधारित संशोधक हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिये आदर्श पूरक हो सकता है।

सेबी द्वारा किये गए नवीन सुधारों का प्रभाव तथा महत्त्व

SEBI ने इस वर्ष की अपनी आखिरी बैठक में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये हैं। इन सुधारों का उद्देश्य आम निवेशकों के हितों की सुरक्षा तथा बाज़ार के विनियमन मानकों को उन्नत करना है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों तथा म्यूचुअल फंड से संबंधित सुधार

- सेबी ने रेटिंग के साथ-साथ म्यूचुअल फंड में हितों के टकराव को दूर करने के मकसद से एक दूसरे में **10 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग की सीमा तय** कर दी है।
- इसका मतलब यह है कि यदि किसी कंपनी या व्यक्ति के पास किसी रेटिंग एजेंसी या म्यूचुअल फंड के **10%** शेयर हैं तो वह किसी दूसरी रेटिंग कंपनी या म्यूचुअल फंड के **10%** से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद पाएगा।
- रेटिंग एजेंसियों की स्थापना के लिये **न्यूनतम कुल मूल्य (Net Worth) सीमा** को **5** करोड़ से बढाकर **25** करोड़ कर दिया है। इससे नई रेटिंग एजेंसी स्थापित करना थोडा मुश्किल हो जाएगा।

लाभ

- यह निर्णय पूरी तरह से लागू होने पर निवेशकों को विभिन्न बाज़ारों में अधिक सुरक्षित और विनियमित तथा अधिक पारदर्शी व्यापार, क्लीयरिंग और निपटान (**Settlement**) ढाँचा उपलब्ध कराएगा।
- भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग मुख्यतः धातुओं और तेलों पर केंद्रित है। कृषि कमोडिटी में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि सेबी के इस कदम से इसका समाधान होने की आशा है।
- केवाईसी (**Know Your Customer-KYC)** में लगने वाले समय की बचत होगी।
- इससे क्रॉस-लिस्टिंग में भी सहायता मिलेगी। जब कोई भी कंपनी अपने शेयरों को एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कराती है तो इसे क्रॉस-लिस्टिंग कहते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ग्रेफीन आधारित बैटरी

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा लिथियम आयन बैटरी की तुलना में पाँच गुना तेज़ गति से कार्य करने वाली एक नई ग्रेफीन आधारित बैटरी विकसित की गई है।

उपयोग

- इस बैटरी का उपयोग अगली पीढ़ी के मोबाइल के साथ–साथ इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- मानक लिथियम बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में कम-से-कम एक घंटा (त्वरित चार्जिंग तकनीक के साथ भी) लगता है।
- ग्रेफीन में निहित सामग्री के विषय में यह पाया गया कि यह एक उच्च शक्ति और चालकता वाली सामग्री है। इसके इसी गुण के कारण यह शोध का प्राथमिक स्रोत बना है।

एक नए सौरमंडल की खोज : जीवन की नई राह

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (National Aeronautics and Space Administration - NASA) द्वारा दो नए एक्सोप्लैनेट्स (केप्लर-90i और केप्लर -80g) की खोज की गई है। यह खोज नासा के केप्लर स्पेस टेलीस्कोप (NASA's Kepler Space Telescope) के आकलन पर आधारित है।

- एक्सोप्लैनेट्स के संदर्भ में अभी तक की नासा की सभी खोजों में यह काफी महत्त्वपूर्ण एवं भिन्न है – इसके दो कारण हैं, पहला यह कि केप्लर-**90i** एक्सोप्लैनेट्स जो कि केप्लर **90 (Kepler 90)** के चारों ओर घूर्णन करता है। यह सूर्य के समान एक अन्य तारा है जिसके चारों ओर आठ ग्रह परिक्रमा करते हैं।
- दूसरा यह है कि इस खोज के लिये गूगल की सहायता ली गई है। गूगल के इंजीनियरों की ओर से आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस (**artificial intelligence)** मशीन की मदद ली गई, जिससे उन ग्रहों को खोजने में मदद मिली जिन्हें अभी तक नहीं खोजा जा सका था।

प्रमुख विशेषताएँ

- हमारे सौरमंडल की तरह ही केप्लर-**90** एक ऐसा सितारा है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं। हमारे सौरमंडल के बाहर खोजा गया यह अब तक का सबसे बड़ा सौरमंडल है।
- हालाँकि इस सौरमंडल का प्रमुख ग्रह **2,545** प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तथापि इसके सभी ग्रह हमारे सौरमंडल की तरह ही क्रम में अवस्थित हैं।
- ऐसा कहा जा सकता है कि केप्लर-**90** के ग्रहों की प्रणाली हमारे सौरंमडल का एक छोटा रूप है। इसके भीतर छोटे और बाहर बड़े ग्रह हैं लेकिन सभी ग्रह एक-दूसरे के करीब अवस्थित हैं।
- इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी कक्षा का अंतिम ग्रह इसके प्रमुख सितारे से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर पृथ्वी से सूर्य है।
- इसके अंतर्गत पृथ्वी जैसे एक अन्य ग्रह केप्लर **80 Kepler 80** की परिक्रमा करने वाले केप्लर **80g (Kepler 80g)** ग्रह के विषय में भी अध्ययन किया गया। खगोलविदों के मुताबिक इन आठ में से एक 'पृथ्वी से सबसे ज़्यादा मिलता-जुलता' ग्रह है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

'जुड़वाँ' धरती

- खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, आठ में से केवल तीन ग्रह ही अपने परिचारक तारे के आवासीय क्षेत्र के भीतर अवस्थित हैं, साथ ही इनमें से केवल एक ग्रह ही पृथ्वी की तरह चट्टानी और थोड़ा गर्म है।
- पृथ्वी से सबसे ज़्यादा मिलते-जुलते इस 'ग्रह' को वैज्ञानिक भाषा में **'केप्लर 438b'** नाम दिया गया है।
- इसके पहले **'केप्लर 186f'** की खोज की गई थी, जिसे पृथ्वी जैसा ग्रह और पृथ्वी का जुड़वाँ ग्रह का नाम दिया गया था। इस खोज के बाद से वैज्ञानिकों द्वारा केप्लर **438b** को पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह माना जा रहा है।
- यह आकार में पृथ्वी से लगभग **12** फ़ीसदी अधिक बड़ा तथा **'केप्लर186f'** से लंबाई एवं चौड़ाई में अधिक है।
- हालाँकि **'केप्लर 438b'** तथा पृथ्वी के तापमान में अधिक समानता पाई गई है।

विदेशी हमले के तहत जैव विविधता

भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण (Zoological Survey of India - ZSI) विभाग द्वारा पहली बार विदेशी आक्रमणकारी प्रजातियों की एक संकलित सूची तैयार की गई है। विदेशी आक्रमणकारी प्रजातियों की इस सूची के अंतर्गत सूक्ष्मजीवों को भी शामिल किया गया है।

कुछ प्रमुख प्रजातियाँ

- पार्थेनियम हिस्टरोफोरस (**Parthenium hysterophorus)** जिसे कपास घास के नाम से भी जाना जाता है और लान्टैना कैमैरा (**Lantana camara)** जैसी कुछ ऐसी प्रमुख विदेशी आक्रमणकारी प्रजातियाँ हैं जो कृषि और जैव विविधता को नुकसान पहुँचाने के लिये जानी जाती हैं।

इनकी प्रवृत्ति आक्रमक क्यों होती है?

- विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि विदेशी प्रजातियों को जान-बूझकर या गलती से उनके प्राकृतिक क्षेत्रों से बाहर लाया जाता है, तो वे 'आक्रामक' हो जाती हैं और जहाँ उन्हें लाया जाता है वे न केवल वहाँ की देशी प्रजातियों को उस स्थान विशेष से बाहर निकाल देती हैं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को भी अस्त-व्यस्त कर देती हैं।
- अचातिना फुलिका (**Achatina fulica)** अथवा अफ्रीकी सेब घोंघा इन सभी विदेशी प्रजातियों में सबसे अधिक आक्रामक माना जाता है। यह एक मॉलस्क है।

इसे पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया था। यह और बात है कि आज यह प्रजाति पूरे देश में पाई जाती है और कई देशी प्रजातियों के निवास के लिये खतरा बन गई है।

2030 तक भारत की हरित निवेश क्षमता $3 ट्रिलियन होने की संभावना

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation) ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि भारत में 2018 से 2030 तक जलवायु के क्षेत्र में 3 ट्रिलियन डॉलर निवेश प्राप्त करने की क्षमता है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में हरित इमारत (**Green Buildings)** निर्माण एक ऐसा क्षेत्र साबित हो सकता है, जो सर्वाधिक निवेश को आकर्षित कर सकता है।
- इसका कारण यह है कि **2030** तक हमें जिस प्रकार की हरित इमारतों की आवश्यकता होगी, उनमें से **70%** का निर्माण किया जाना अभी शेष है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विभिन्न क्षेत्रों में हरित निवेश की संभावना

बाधाएँ

IFC की रिपोर्ट भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ बाधाओं की भी बात करती है, जिसे नीचे दर्शाए गए रेखाचित्र से समझ सकते हैं-

तुलनात्मक अध्ययन

पाकिस्तान को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देश भी हरित निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं।

- बांग्लादेश- **$ 172** बिलियन
- नेपाल - **$ 46** बिलियन
- भूटान- **$ 42** बिलियन
- श्रीलंका- **$ 18** बिलियन
- मालदीव- **$ 2** बिलियन

निष्कर्ष

भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 2005 के उत्सर्जन की तुलना में 35% घटाने का संकल्प लिया है। अतः भारत को अपने इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति के लिये विभिन्न क्षेत्रों जैसे-कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना तथा परिवहन में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी।

पेट्रोलियम-कोक का आयात और प्रदूषण की समस्या

पर्यावरण विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि भारत में पेट्रोलियम कोक या Pet-Coke का बढ़ता आयात देश में वायु-प्रदूषण की समस्या को और अधिक बढ़ा देगा। पेट-कोक का सर्वाधिक इस्तेमाल सीमेंट-कारखानों द्वारा किया जाता है।

पेट-कोक क्या है?

पेट-कोक पेट्रोलियम रिफाइनिंग की प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ उच्च-सल्फर और उच्च कार्बन कंटेंट वाला सह-उत्पाद है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान जो सल्फर, ईंधन से अलग किया जाता है, वह पेट-कोक जैसे अपशिष्ट उत्पादों में पहुँच जाता है।

पेट-कोक की विशेषताएँ

- यह उच्च-कार्बन**,** उच्च-सल्फर और निम्न राख **(ash)** कंटेंट वाला उत्पाद है। इसका कैलोरिफिक मान अधिक होता है और लागत कम होती है।
- इसकी हैंडलिंग लागत भी कम होती है।
- पेट-कोक और साधारण कोयले की समान मात्रा के दहन के बाद पेट-कोक से कहीं ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- पेट-कोक के दहन में अपेक्षाकृत कम वायु की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त विशेषताओं के कारण उद्योगों में ऊष्मीय उर्जा के उत्पादन के लिये पेट-कोक काफी प्रचलित ईंधन है। भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग सीमेंट-फैक्ट्रियों द्वारा किया जाता है।

समुद्री जगत में स्वच्छ पर्यावरण की महत्ता

एक अध्ययन के अनुसार, एक विशेष प्रकार के समुद्री जीव में एक प्लास्टिक बैग को तकरीबन 10 लाख टुकड़ों में विखंडित करने की क्षमता मौजूद होती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- प्लाईमाउथ विश्वविद्यालय (**University of Plymouth**) के समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा यह पाया गया कि **एम्पिपोड ऑर्केस्टिया गैमारेल्लस (Amphipod Orchestia gammarellus)** नामक समुद्री जीव में प्लास्टिक बैग को विखंडित करने की क्षमता है।
- यह समुद्री जीव उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है।

मुख्य उद्देश्य

- इस शोध से प्राप्त नतीजों के अनुसार, वास्तविकता यह है कि समुद्री वन्यजीव समुद्री वातावरण के भीतर सूक्ष्म प्लास्टिक के प्रसार में योगदान कर रहे हैं।
- ये जीव पानी की आपूर्ति से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण अथवा बड़े मदों वाले भौतिक एवं रासायनिक विघटन के माध्यम से निर्मित प्रदूषण की तुलना में अधिक प्रदूषण का प्रसार करते हैं।

पराली जलाने की समस्या से निपटने हेतु क्षेत्रीय परियोजना

जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों में जलवायु सुदृढ़ता निर्माण पर एक क्षेत्रीय परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में परियोजना को स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन सचिव द्वारा की गई।
- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के लिये लगभग **100** करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण को स्वीकृति दी गई है।

उद्देश्य

- इस परियोजना का उद्देश्य न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मिटाना और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देना है, बल्कि पराली जलाने से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों से निपटना भी है।
- इसके अंतर्गत सबसे पहले किसानों को वैकल्पिक व्यवहारों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कार्य के लिये जागरुकता अभियान और क्षमता सृजन गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।
- वैकल्पिक व्यवहारों से किसानों के आजीविका विकल्पों को बढ़ाने में मदद मिलेगी और उनकी आय भी बढ़ेगी।

वैश्विक संदर्भ में

- विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, विश्व में होने वाली हर आठ मौतों में से एक वायु प्रदूषण के कारण होती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग **65** लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं।
- लांसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष **460** लाख डॉलर प्रदूषण जनित रोगों पर खर्च होते हैं, जो विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग **6.2%** है।

पराली क्या होती है?

- पराली धान की फसल कटने के बाद बचा बाकी हिस्सा होता है, जिसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं। किसान धान पकने के बाद फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं क्योंकि वही काम का होता है बाकी किसान के लिये बेकार होता है।
- उन्हें अगली फसल बोने के लिये खेत खाली करने होते हैं तो सूखी पराली को आग के हवाले कर दिया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सामाजिक मुद्दे

केरल की जनजातियों में पारंपरिक ज्ञान और अस्तित्व कौशल का संकट

केरल की जनजातीय आबादी में पीढ़ियों से बसा पारंपरिक ज्ञान अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में ज्ञान हस्तांतरण की प्रक्रिया में अब कमी आती जा रही है। युवा पीढ़ी नई तकनीकी जानकारियों एवं सूचनाओं के साथ सामंजस्य बिठाने की जुगत में अपनी पारंपरिक शैली से दूर होती जा रही है।

आई.आई.आई.टी.एम-के. की रिपोर्ट

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, (Indian Institute of Information Technology and Management-Kerala – IIITMK), केरल द्वारा आयोजित किये गए एक अध्ययन में इस बारे में जानकारी प्रदान की गई कि केरल के आदिवासी युवाओं, विशेष रूप से पुरुषों के बीच पारंपरिक रूप से विरासत में मिली परंपराओं के संग्रहण की क्षमता में निरंतर गिरावट आ रही है।

प्रमुख बिंदु

भारत में अपनी तरह का यह पहला अध्ययन है जिसके अंतर्गत पारंपरिक ज्ञान के संबंध में एक मात्रात्मक अनुमान प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन के अनुसार, पश्चिमी घाट के आठ जनजातीय समुदायों के बीच पारंपरिक ज्ञान के संग्रहण में आ रही गिरावट लुप्तप्राय स्थिति में है।

ज्ञान की घटती स्थिति

- अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के मुताबिक, कुरिच्यार और कुरुम्बा (**Kurumba**) जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान का आधे से भी अधिक भाग नष्ट हो चुका है।
- इसी प्रकार चोलनाईकर और मलापंदारम जनजातियाँ अपने पारंपरिक ज्ञान का तकरीबन **33** प्रतिशत भाग गवाँ चुकी हैं।
- इसी प्रकार काणी (**Kaani**) और कट्टुनाईकर जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान का लगभग **40** से **45** प्रतिशत अंश नष्ट हो चुका है।
- इन सबमें मलापंदमार जनजाति के एक ऐसा समुदाय है जिसके पास इस समय सबसे कम पारंपरिक ज्ञान है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

रिपोर्ट, योजनाएँ एवं कार्यक्रम

आर्थिक असमानता में हो रही लगातार वृद्धि: विश्व असमानता रिपोर्ट

"वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब' ने अपनी पहली 'विश्व असमानता रिपोर्ट' (World Inequality Report) जारी की है, जिसके आँकड़े पूरे विश्व के लिये चिंताजनक हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग सभी देशों में आर्थिक असमानता बढ़ रही है।

क्या है यह रिपोर्ट?

वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब से जुड़े विख्यात अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट को 1980 से 2016 के बीच के 36 वर्षों के वैश्विक आँकड़ों को आधार बनाकर तैयार किया गया है।

क्या कहती है 'विश्व असमानता रिपोर्ट' ?

- इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के **0.1%** लोगों के पास दुनिया की कुल दौलत का **13%** हिस्सा है।
- निजीकरण और आय की असमानता के चलते संपत्ति के वितरण में भी असमानता में वृद्धि हुई है।
- इस रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है कि यदि उभरते हुए देश **1980** के बाद की नीतियाँ ही जारी रखते हैं**,** तो भविष्य में आर्थिक असमानता के और अधिक बढ़ने की संभावना है।

भारत के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट?

- इस रिपोर्ट के अनुसार **2014** में भारत के शीर्ष **1%** अमीरों के पास राष्ट्रीय आय की **22%** हिस्सेदारी थी और शीर्ष **10%** अमीरों के पास **56%** हिस्सेदारी थी।
- देश के शीर्ष **0.1%** सबसे अमीर लोगों की कुल संपदा बढ़कर निचले **50%** लोगों की कुल संपदा से अधिक हो गई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विविध

रानी रुद्रमा देवी की मूर्तियाँ और उससे जुड़े पक्ष

हाल ही में तेलंगाना के वारंगल ज़िले के बोलीकुंटा (Bollikunta) गाँव से भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (Archaeological Survey of India - ASI) द्वारा दक्षिण भारत की मध्ययुगीन वीरांगना रानी रुद्रमा देवी (शासनकाल 1262–89 A.D.) की ग्रेनाइट से बनी दो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। संभवतः इस खोज से रानी की मौत के पीछे का रहस्य उजागर हो सकता है।

मुद्दा क्या है?

- काफी लंबे समय से यह सवाल शोध का विषय रहा है कि **13**वीं शताब्दी की साहसी काकतीय रानी (काकतीय वंश **11** से **13** वीं शताब्दी **A. D.)** का अंत आखिर किस प्रकार हुआ।
- हालाँकि इससे पहले नलगोंडा ज़िले से प्राप्त हुए एक शिलालेख में रानी के निधन स्थान के रूप में चन्दुपटला **(Chandupatla)** को चिन्हित किया गया था।

क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई मूर्तियाँ

- हालाँकि ये दोनों मूर्तियाँ मानवीय उपेक्षा और प्रकृति की अनियमितताओं के कारण बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं।
- ये मूर्तियाँ न केवल एतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण हैं बल्कि इनसे उस विशेष समयकाल में घटित घटनाओं के विषय में (युद्ध, मृत्यु, युद्ध के पश्चात् के जीवन इत्यादि के विषय में) महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी।

रानी रुद्रमा देवी कौन थी?

- रुद्रमा देवी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। इनका जन्म गणपति देव के यहाँ हुआ था।
- राजा गणपति का कोई पुत्र नहीं था इसलिये पिता की मृत्यु के पश्चात् रुद्रमा देवी ने शासन किया। जब इन्होंने शासन संभाला उस समय वह मात्र **14** वर्ष की थीं।
- उन्हें वारंगल के किले को पूरा करने, तेलंगाना में सिंचाई टैंक प्रणाली की श्रृंखला को शुरू करने, अस्पतालों की स्थापना करने और सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु पेरीनी शिव तांडवम (**Perini Shiva Tandavam)** नृत्य कला का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार **(National Service Scheme – NSS Awards)** 2016-17 प्रदान किये गए।

उद्देश्य

- एन.एस.एस. पुरस्कारों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, सीनियर सेकेंडरी (+**2)** परिषदों, एन.एस.एस. इकाइयों/कार्यक्रम अधिकारियों और एन.एस.एस. स्वंयसेवकों द्वारा स्वंयसेवी सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में दिये गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना एवं उन्हें पुरस्कृत करना है, ताकि एन.एस.एस. को आगे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके।
- उपर्युक्त पुरस्कारों के अलावा कभी-कभी अत्यन्त सीमित संख्या में नामितों को प्रशस्ति पत्र भी दिये जाते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय सेवा योजना का परिचय

- एन.एस.एस. केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इस योजना का शुभारंभ वर्ष **1969** में किया गया था।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवी सामुदायिक सेवा के ज़रिये युवा विद्यार्थियों में व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास करना है।

अपतटीय निगरानी जहाज़ आई.सी.जी.एस. सुजय

भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अपतटीय निगरानी जहाज़ों (Offshore Patrol Vessel - OPV) की श्रृंखला के छठे भारतीय तटरक्षक जहाज़ सुजय (Indian Coast Guard Ship "Sujay) को तैनात किया गया।

सुजय का अर्थ

- सुजय का अर्थ है **'महान विजय' (Great Victory)**। यह भारतीय तटरक्षक (**Indian Coast Guard**) की इच्छाशक्ति और संकल्प को अभिव्यक्त करता है।
- इस जहाज़ में अत्याधुनिक नौवहन तथा संचार उपकरण, सेंसर तथा मशीनरी लगी हुई है।

उपयोगिता

- इतना ही नहीं यह जहाज़ समुद्र में तेल बिखराव को नियंत्रित करने के लिये प्रदूषण अनुक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है।
- पारादीप में तटरक्षक बेड़े में शामिल होने के बाद इस जहाज़ को ईईजेड निगरानी तथा भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिये तटरक्षक चार्टर में दिये गए कर्त्तव्यों के लिये तैनात किया जाएगा।

वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, 2018

हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल आर्गेनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन (International Organization for Migration- IOM) द्वारा वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, 2018 जारी की गई। यह रिपोर्ट वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट की श्रृंखला की नौवीं रिपोर्ट है। यह संगठन दुनिया भर में प्रवासन के संबंध में समझ में वृद्धि करने की दिशा में काम कर रहा है। इसी संदर्भ में यह संगठन विश्व प्रवासन रिपोर्ट तैयार करता है।

पृष्ठभूमि

- आई.ओ.एम. प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी एक अंतर-सरकारी संगठन है।

मुख्य कार्य क्षेत्र

- आईओएम प्रवासन प्रबंधन के चार व्यापक क्षेत्रों में काम करता है-
  - ⇒ प्रवासन और विकास
  - ⇒ प्रवासन को सुगम बनाना
  - ⇒ प्रवासन विनियमन
  - ⇒ हठात् प्रवासन (Forced Migration)
- इस रिपोर्ट के अनुसार, तकरीबन **15** मिलियन से अधिक आबादी के साथ भारतीय प्रवासियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। मैक्सिको और रूस क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- विदेशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या के संदर्भ में भारत शीर्ष पर है। लगभग **16.59** मिलियन भारतीय लोग विदेश में रहते हैं। इसके बाद **13** मिलियन प्रवासियों के साथ मैक्सिको दूसरे स्थान पर है।
- भारतीय प्रवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या (वर्ष **2000** के अनुसार, **3.31** मिलियन) संयुक्त अरब अमीरात में वास करती है**,** इसके बाद अमेरिका (**2.3** मिलियन) का स्थान आता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पीआईबी स्पेशल

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट

पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मिलकर 5 से 7 दिसंबर, 2017 तक गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा।
- इसके साथ-साथ 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के उद्देश्यों के तहत आसियान देशों के साथ भारतीयों के आपसी संपर्क में वृद्धि करने के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे आसियान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर-क्षेत्रीय पर्यटन को विकसित करने में मदद मिलेगी।
- छठे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन की संभावना को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के सामने प्रस्तुत करना है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट

- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन पूर्वोत्तर राज्यों में बारी-बारी से किया जाता है। इससे पूर्व मार्ट का आयोजन गुवाहाटी, तवांग, शिलांग, गंगटोक और इम्फाल में किया जा चुका है।
- घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित यह छठा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम है।
- विदेशी प्रतिनिधियों के अलावा देश के अन्य भागों से पर्यटन क्षेत्र के **50** घरेलू पणधारी तथा पूर्वोत्तर राज्यों से **86** विक्रेता इस मार्ट में भाग ले रहे हैं।

ई-कोर्ट परियोजना पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के न्याय विभाग के सहयोग से उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी द्वारा 2 और 3 दिसंबर को नई दिल्ली में दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

ई-कोर्ट मिशन क्या है?

- ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना देश में ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी के ज़रिये सशक्त करके इन्हें राष्ट्रीय ई-अभिशासन परियोजना के दायरे में लाने हेतु चलाई गई एक मिशन मोड परियोजना है।

उद्देश्य

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- समूची न्यायिक प्रणाली को सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी से समन्वित करने हेतु सम्पर्क कायम करना।
- सभी न्यायालयों में कार्यप्रवाह का स्वचालित प्रबंधन करना।
- हर न्यायालय परिसर में टच स्क्रीन आधारित क्योस्क (**kiosks**) की स्थापना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

बौद्ध विरासत का बिम्सटेक उत्सव : बोधि पर्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिम्सटेक की 20वीं वर्षगाँठ के अवसर पर भारत सरकार द्वारा 'बोधि पर्व: बौद्ध विरासत का बिम्सटेक महोत्सव' के 2017 संस्करण का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन एम.ई.ए. (Ministry of External Affairs - MEA) द्वारा किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 'बोधि पर्व' के अंतर्गत बौद्ध विरासत की घनिष्ठ परंपरा दर्शाई गई है।
- इस दौरान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कलाओं और वास्तु की प्रदर्शनी, विशिष्ट शिक्षाविदों और बौद्ध धर्म के अनुयाइयों के बीच संवाद, बौद्ध संन्यासियों द्वारा बौद्ध धर्म के संदेशों का पाठ और चिंतन, बौद्ध धर्म पर फिल्मों का प्रदर्शन, नृत्य एवं संगीत, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ एवं खान-पान के स्टॉल भी लगाए गए।
- इसका उद्देश्य बिमस्टेक देशों की समृद्ध और समान परपंरा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है।
- 'बोधि पर्व' जैसे उत्सवों से बिमस्टेक के संवर्द्धन में बहुत मदद मिलेगी।

बिम्सटेक क्या है?

- एक उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समूह के रूप में बिम्सटेक (बांग्लादेश, भारत, म्याँमार, श्रीलंका और थाइलैंड तकनीकी और आर्थिक सहयोग) का गठन जून **1997** में बैंकॉक में किया गया था।
- दिसंबर **1997** में म्याँमार तथा फरवरी **2004** में भूटान और नेपाल भी इस समूह में शामिल हो गए। इस संगठन की तात्कालिक प्राथमिकता अपने कार्यकलापों को समेकित करना तथा आर्थिक सहयोग के लिये इसे आकर्षक बनाना है।

भू-जल दृष्टिकोण 2030: गिरते भू-जल स्तर की चुनौतियाँ

संदर्भ

राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान, रुड़की और केंद्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB) द्वारा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तत्त्वावधान में देश में भू-जल के मुद्दे पर नई दिल्ली में 11 से 13 दिसंबर तक एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन का शीर्षक था- 'भू-जल दृष्टिकोण **2030**-जल सुरक्षा, चुनौतियाँ और जलवायु परिवर्तन अनुकूलता'।
- इस सम्मेलन में **15** देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और **250** शोध पत्र प्रस्तुत किये गए, जिनमें से **32** मुख्य सिद्धांत पर आधारित थे।
- इस सम्मेलन में देश में पानी के इस्तेमाल और बदलते जलवायु परिदृश्य के अंतर्गत भू-जल की वर्तमान स्थिति और उसके प्रबंधन की चुनौतियों का जायज़ा लिया गया।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण

- वर्ष **1970** में कृषि मंत्रालय के तहत समन्वेषी नलकूप संगठन को पुन:नामित कर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की स्थापना की गई थी ।
- यह प्राधिकरण उद्योगों/बुनियादी ढाँचा/खनन परियोजनाओं के वास्ते भूजल निकालने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस प्राधिकरण को देशभर के भूजल संसाधनों के अन्वेषण, निगरानी, आकलन, संवर्द्धन एवं विनियमन हेतु वैज्ञानिक संभरण उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है।
- प्राधिकरण भू-जल में कमी, समुद्री जल अंत:प्रवेश, भूजल संदूषण, सतही एवं भूजल का संयुक्त उपयोग, जल संतुलन आदि भूजल संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विशिष्ट अध्ययन भी करता है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने के लिये मंज़ूरी दी गई।

विशेषताएँ

राष्ट्रीय आयुष मिशन का क्रियान्वयन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
राष्ट्रीय आयुष मिशन देश में और खासतौर से कमजोर एवं दूरदराज के इलाकों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएँ/शिक्षा उपलब्ध कराकर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों को समर्थन दे रहा है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के अंतराल को दूर किया जा सके।

बागवानी फसलों तथा फलों के सकल उत्पादन में विश्व में भारत का द्वितीय स्थान

पी.आई.बी. द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, पिछले कई वर्षों में बागवानी फसलों पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का बड़ा उत्साहजनक परिणाम रहा है, जिसके फलस्वरूप लगातार चार वर्षों से प्रतिकूल जलवायु की दशाओं में भी बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्य फसलों से अधिक रहा है। चीन के बाद भारत का बागवानी फसलों तथा फलों के सकल उत्पादन में द्वितीय स्थान है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष **2015-16** की अवधि में कुल **63** लाख हेक्टेयर भूमि से नौ करोड़ मीट्रिक टन से अधिक फलों का उत्पादन हुआ था।
- भारतवर्ष में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से नीबू वर्गीय फलों का दूसरा (**10.37** लाख हेक्टेयर) एवं उत्पादन की दृष्टि से तीसरा (**1.2** करोड़ टन) स्थान है।

एकीकृत बागवानी मिशन परियोजना

- पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने एवं पर्यावरण को विशुद्ध करने में फलों एवं बगीचों के महत्त्व को ध्यान में रखकर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत बागवानी मिशन परियोजना चलाई जा रही है।

'सखी' वन - स्टॉप केंद्र

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) द्वारा महिला हिंसा के खिलाफ बहु-क्षेत्रवार कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने में 'सखी' वन-स्टॉप केंद्रों (Sakhi One Stop Centres) की भूमिका पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह देश भर में 'सखी' वन स्टॉप केंद्रों के ज़रिये महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने से संबंधित बहु-क्षेत्रवार कार्रवाई (**multi-sector response)** को सुदृढ़ बनाने के उपायों को समझने, उन पर चर्चा तथा विचार-विमर्श करने से संबद्ध पहल है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा **4** मार्च, **2015** को हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर में वन-स्टॉप केंद्रों की स्थापना की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- सखी के रूप में लोकप्रिय इस योजना का कार्यान्वयन **1** अप्रैल, **2015** से किया जा रहा है।

लक्ष्य

- इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को चिकित्सकीय सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी मदद/केस प्रबंधन तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श समेत एकीकृत सेवाएँ प्रदान करना है।
- इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अस्थाई समर्थन सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2017 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

पर्यटन के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन निरंतर सकारात्मक रहा है। कुछ समय पहले जारी किये गए यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2017 (Travel & Tourism Competitiveness Index - TTCI) में पर्यटन के क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन के संबंध में यह बात साबित भी हुई। इस सूचकांक में भारत वर्ष 2013 की तुलना में 25 पायदान ऊपर पहुँच गया है, क्योंकि टी.टी.सी.आई. रिपोर्ट 2017 में भारत का 40वाँ स्थान है, जबकि 2015 में यह 52वें तथा 2013 में 65वें स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के विकास एवं प्रोत्साहन से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माण के लिये मुख्य नोडल एजेंसी है।
- इन सभी कार्यों के लिये मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों, राज्य सरकारों/केंद्र-शासित प्रशासनों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करता है तथा आवश्यक सहयोग भी प्रदान करता है।

पर्यटन अवसंरचना का विकास

- स्वदेश दर्शन योजना (**Swadesh Darshan Scheme)** के अंतर्गत थीम आधारित पर्यटन यात्रा मार्गों को विकसित किया गया है।
- राष्ट्रीय तीर्थस्थल पुन:स्थापना और आध्यात्मिक, विरासत विकास मिशन (**National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive' - PRASHAD)** योजना के अंतर्गत तीर्थस्थलों की पहचान करके समग्र विकास करने के कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।

पर्यटन केंद्रों का समग्र विकास

- पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन केंद्रों पर विश्वस्तरीय सुविधाएँ प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता में रखा गया है। इसके अंतर्गत अवसंरचना का विकास, जनसुविधाएँ, बहुभाषा केंद्र तथा कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग जगत के हितधारकों के साथ मिलकर 'विरासत गोद लें' **(Adopt A Heritage project)** नाम से एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है।
- इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत स्तर पर भी इन स्थलों में सुविधाएँ विकसित करने का भी कार्य किया जाएगा। ऐसा करने वालों को 'स्मारक मित्र' **(Monument Mitras)** के नाम से संबोधित किया जाएगा।
- राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करके पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस नई योजना के लिये दिशा-निर्देश तैयार किये गए हैं। विशेष पर्यटन क्षेत्र के निर्माण से क्षेत्र विशेष का समग्र विकास किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इन प्रयासों से जहाँ एक ओर आजीविका के अवसरों का निर्माण होगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

पर्यटन पर्व (Paryatan Parv)

- अक्तूबर **2017** को **31** राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों में पर्यटन पर्व का आयोजन किया गया। इसमें देश की सांस्कृतिक विभिन्नता को दर्शाया गया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन के लाभों को रेखांकित करना था।
- इस कार्यक्रम की मुख्य थीम 'सभी के लिये पर्यटन' थी।

भारत पर्व (Bharat Parv)

- पर्यटन मंत्रालय को भारत सरकार द्वारा लाल किले पर गणतंत्र दिवस आयोजन के एक भाग के रूप में **26** से **31** जनवरी, **2017** तक आयोजित भारत पर्व कार्यक्रम के लिये नोडल मंत्रालय बनाया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न भागों से गणतंत्र दिवस परेड, झाकियाँ, सशस्त्र बल बैंडों द्वारा प्रस्तुति, फूड फेस्टिवल, शिल्प मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा **5-7** दिसंबर, **2017** तक गोवाहाटी, असम में छठा अंतर्राष्ट्रीय मार्ट (**World Travel Mart - WTM**) आयोजित किया गया।

गोवा में तीन रेलवे स्टेशनों पर पर्यटन संबंधी सुविधाओं का विकास

- कोंकण रेलवे यात्रा, अपने सुंदर परिदृश्यों के कारण देश की सबसे यादगार ट्रेन यात्राओं में से एक है।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन दृष्टिकोण से कोंकण रेलवे के महत्त्व पर विचार करते हुए गोवा में मडगाँव, कारमली और थिविम रेलवे स्टेशनों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिये **2499.98** लाख रुपए स्वीकृत किये गए हैं।

काँच की छत वाले डिब्बे

- इन सबके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय द्वारा अपनी रेल पर्यटन नीति के तहत तीन काँच वाले डिब्बे बनाने के लिये रेल मंत्रालय के साथ कार्य किया जा रहा है। इन डिब्बों को देश के प्राकृतिक दृश्यों वाले मार्गों पर संचालित किया जाएगा।
- काँच की छत वाले इन डिब्बों में अधिक चौड़े, आरामदायक बैठने के स्थान, बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ और एक किनारे पर एक तरफ से दिखाई देने वाली खिड़कियाँ, काँच की छत, घूमने वाली सीटें, स्वचालित सरकने वाले दरवाज़े, छोटी पेंट्री और चौड़े दरवाज़े लगाए गए हैं।

वर्ष 2017 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल एवं उपलब्धियाँ

वर्ष 2017 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum & Natural Gas) द्वारा आरंभ की गई पहलों एवं उपलब्धियों के संबंध में एक वार्षिक ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। इस ब्योरे में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए आँकड़ाबद्ध सूचनाएँ प्रदान की गई हैं।

अन्वेषण और उत्पादन (Exploration & Production)

एचईएलपी (HELP)

- इस नीति को **01** जुलाई, **2017** से प्रभावी बनाकर औपचारिक रूप से जारी कर दिया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय आँकड़ा संग्रहण (National Data Repository - NDR)

- डीजीएच ने एनडीआर की स्थापना की, ताकि व्यापारिक अन्वेषण, अनुसंधान, विकास और अकादमिक उद्देश्यों के लिये अन्वेषण और उत्पादन आँकड़े उपलब्ध हों।

प्राकृतिक गैस

राष्ट्रीय गैस ग्रिड (प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा) National Gas Grid (Pradhan Mantri Urja Ganga):

- गैस आधारित अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बास्केट में गैस का हिस्सा **15** प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने **15** हज़ार किलोमीटर अतिरिक्त गैस पाइप लाइन नेटवर्क के विकास का मंसूबा बनाया है।
- इस समय देश में प्राकृतिक गैस ग्रिड पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण-पूर्वी गैस बाज़ार को जोड़ता है। ये क्षेत्र प्रमुख गैस संसाधन वाले क्षेत्र हैं।

शहरी गैस वितरण (सीजीडी) तंत्र (City Gas Distribution Network)

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में **27** मार्च, **2015** को आयोजित ऊर्जा संगम, **2015** में उल्लेख किया था कि अगले चार वर्षों के दौरान शहरों में प्रदूषण में कमी लाने के लिये पाइप लाइन गैस कनेक्शनों को **28** लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाएगा।
- इस समय **31** सीजीडी कंपनियाँ **21** राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के **81** स्थानों में सीजीडी तंत्र का विकास कर रही हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY):

- यह योजना पाँच करोड़ बीपीएल (**Below Poverty Line-BPL**) महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने के लिये शुरू की गई थी

एलपीजी दायरा

- वर्ष **2016-17** के दौरान **3.31** करोड़ से अधिक नए एलपीजी कनेक्शन दिये गए। इसी तरह **2017-18** (**18** दिसंबर, **2017** तक) के दौरान **2.15** करोड़ से अधिक नए एलपीजी कनेक्शन दिये गए।
- **01** नवंबर, **2017** को राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज **11** जनवरी, **2015** के **60.6** प्रतिशत से बढ़कर **78.3** प्रतिशत तक पहुँच गया है।
- एलपीजी दायरे को और बढ़ाने के लिये देश के विभिन्न राज्यों में **6,149** नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का विज्ञापन दिया गया, जिसकी चयन प्रक्रिया चल रही है। **19** दिसंबर, **2017** को **2,468** स्थानों का ड्रॉ किया गया है।

ऑटो-ईंधन विज़न (Auto Fuel Vision)

ऑटो-ईंधन विज़न एवं नीति – देश में बीएस-4 और बीएस-6 ईंधन की शुरुआत

- सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से **01** अप्रैल, **2017** से पूरे देश में बीएस-**4** ऑटो-ईंधन की आपूर्ति शुरू कर दी गई है।
- सरकार ने यह भी फैसला किया है कि बीएस-**4** से सीधे बीएस-**6** वर्ग का ईंधन लागू किया जाएगा, जो पूरे देश में **01** अप्रैल, **2020** से कार्यान्वित किया जाएगा।
- इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बहरहाल, दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीएस-**6** को **01** अप्रैल, **2018** से लागू कर दिया जाए।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

ईबीपी कार्यक्रम (EBP Programme)

- इथेनॉल की उपलब्धता सुधारने के लिये सरकार द्वारा **2017-18** के संदर्भ में इथेनॉल आपूर्ति के लिये कीमतों की समीक्षा की गई है और उसे **40.85** रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।
- वर्ष **2015-16** के दौरान तेल विपणन कंपनियों ने **30** नवंबर, **2016** तक **111** करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद की, जो एक रिकॉर्ड है।
- वर्ष **2016-17** के लिये तेल विपणन कंपनियों द्वारा **278** करोड़ लीटर इथेनॉल के लिये संविदा जारी की गई, जिसमें से **14** नवंबर, **2017** तक **62.32** करोड़ लीटर इथेनॉल प्राप्त किया गया।

बॉयो-डीज़ल कार्यक्रम (Biodiesel Programme)

- सरकार द्वारा **29** जून, **2017** की अधिसूचना के ज़रिये बॉयो-डीजल (**Biodiesel -100)** की सीधी बिक्री का रास्ता खोल दिया गया है।
- इसे हाईस्पीड डीज़ल के साथ मिलाया जाएगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो (**Bureau of Indian Standards – BIS)** के मानकों के अनुरूप होगा।

लिग्नोसेल्युलोसेस रूट के ज़रिये दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल (2nd Generation Ethanol through Lignocelluloses Route)

- सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा देश के **11** राज्यों में बारह **2**जी इथेनॉल संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में तेल विपणन कंपनियों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं (पाँच समझौते)/राज्य सरकार (एक समझौता) के साथ छह समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- ये संयंत्र पाँच स्थानों पर लगाए जाएंगे। पहले जैव-ईंधन शोधन संयंत्र की आधारशिला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (**Hindustan Petroleum Corporation Limited**) ने भटिंडा, पंजाब में रखी।

स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission)

- स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता से संबंधित संशोधित प्रावधानों को 'प्रमुख अनियमितता' (**Major irregularity)** के तहत वर्गीकृत किया गया है और तेल विपणन कंपनियों ने जुर्माना प्रावधानों को भी तर्कसंगत रूप से संशोधित किया गया है।
- वर्तमान में देश भर में तेल विपणन कंपनियों के लगभग **55,413** खुदरा बिक्री केंद्र हैं, जिनमें से **54,411** खुदरा बिक्री केंद्रों में शौचालय सुविधा उपलब्ध है।
- इनमें से **30,886** खुदरा बिक्री केंद्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिये अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है।
- तेल विपणन कंपनियों द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सभी खुदरा बिक्री केंद्रों में महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग शौचालय सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिये।

Copyright– Drishti The Vision Foundation